मुंबई (महाराष्ट्र) से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

उत्तरशक्ति

हर खबर निष्पक्षता के साथ

मुंबई
वर्ष: 9 अंक 87
बुधवार, 07 अक्टूबर 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

सुप्रीम कोर्ट को मिले तीन नए जज, सीजेआई सूर्यकांत ने दिलाई शपथ; 37 हुई न्यायाधीशों की संख्या

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को तीन नवनियुक्त न्यायाधीशों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालच में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। इसमें सीजेआई सूर्यकांत भी शामिल हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 38 है।भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को पद की शपथ दिलाई। तीन नए न्यायाधीशों के शपथग्रहण के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश का पद खाली रह गया है। इससे पहले सर्वोच्च अदालत में सीजेआई समेत कुल 34 न्यायाधीश कार्यरत थे।

इससे एक दिन पहले केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया था कि राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत से विचार-विमर्श के बाद तीनों मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से तीनों मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की सिफारिश के कुछ दिनों बाद हुई हैं। कॉलेजियम ने गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल के नाम की सिफारिश की थी, जिनका मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के नाम की सिफारिश की गई थी, उनका मूल

हाईकोर्ट भी इलाहाबाद है। वहीं, तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह का मूल हाईकोर्ट झारखंड है।

जस्टिस सुनीता अग्रवाल का जन्म 30 अप्रैल 1966 को हुआ था। उन्हें 21 नवंबर 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके बाद वह 23 जुलाई 2023 को गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनीं। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय का जन्म 16 जून 1965 को हुआ था। उन्हें 21 नवंबर 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 6 अगस्त 2013 को वह स्थायी न्यायाधीश बने। वह 28 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के वरिष्ठ न्यायाधीश बने।

इसके बाद जस्टिस उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उन्होंने 29 जुलाई 2023 को शपथ ली। बाद में उनका तबादला दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया गया, जहां उन्होंने 21 जनवरी 2025 को पद की शपथ ली। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह का जन्म 7 जुलाई 1965 को हुआ था। उन्हें 24 जनवरी 2012 को झारखंड हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 16 जनवरी 2014 को वह स्थायी न्यायाधीश बने थे। वह 20 दिसंबर 2022 से 19 फरवरी 2023 तक झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे। इसके बाद उन्होंने 17 अप्रैल 2023 को त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बाद में उनका तबादला तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया गया, जहां उन्होंने 19 जुलाई 2025 को शपथ ली।

यूपी: भाजपा के आठों राज्यसभा उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन, सीएम योगी भी रहे मौजूद

लखनऊ, 06 अक्टूबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सान्निध्य में राज्यसभा चुनाव के लिए मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सभी आठों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान, श्रुति गंगवार ने विधान भवन में नामांकन दिया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दीं। पर्चा दाखिला के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री/भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, राकेश सचान, आशीष पटेल, डॉ. संजय निषाद, कपिलदेव अग्रवाल, जेपीएस राठौर, दिनेश प्रताप सिंह, गिरीश चंद्र यादव, ब्रजेश सिंह, सतीश चंद्र शर्मा,

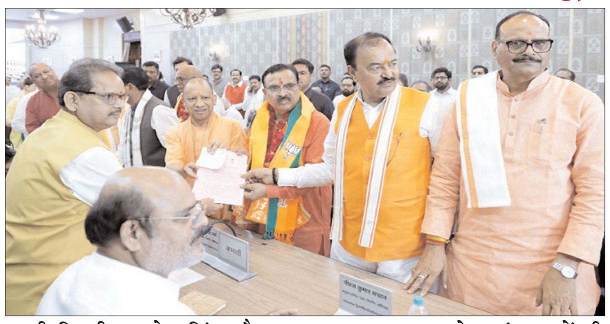

रजनी तिवारी, बलदेव सिंह औलख आदि मौजूद रहे। मंगलवार सुबह आठों प्रत्याशी भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। उनके पहुंचते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुट गए। ढोल-नगाड़ों के साथ प्रत्याशियों का स्वागत किया गया। इसके बाद सभी उम्मीदवार समर्थकों और पार्टी नेताओं के साथ विधानभवन के लिए रवाना हुए। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है। इसके बाद 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 16 अक्टूबर को होगा।

राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवाणी पहले ही नामांकन कर चुके हैं। मंगलवार को अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि सपा तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। इससे उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव का मौजूदा समीकरण और स्पष्ट हो गया है।

हॉर्मुज में फिर भारतीयों से भरे जहाज पर अटैक; प्रोजेक्टाइल गिरने से 11 नाविक घायल, भड़का भारत का गुस्सा

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल हॉर्मुज जलडमरूमध्य में एक और वाणिज्यिक जहाज प्रोजेक्टाइल की चपेट में आ गया। ओमान के तट के पास हुए इस हमले में 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए, जिनमें 11 भारतीय नाविक हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, घायल नाविकों को ओमानी अधिकारियों की मदद से सुरक्षित निकालकर खसब पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी ऑन पीस पर मंगलवार को प्रोजेक्टाइल आकर लगा। उस समय जहाज हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा था। जहाज पर कुल 19 चालक दल के

सदस्य थे, जिनमें 17 भारतीय नागरिक शामिल हैं। हमले में 12 सदस्य घायल हुए और इनमें 11 भारतीय नाविक हैं। घायल सभी लोगों को ओमान के अधिकारियों की सहायता से बाहर निकाला गया और चिकित्सा उपचार के लिए खसब ले जाया गया।

भारत ने वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले की निंदा की है और राहत एवं बचाव में सहायता के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में समुद्री जहाजों पर लगातार हो रहे हमले गंभीर चिंता का विषय हैं और शांति तथा स्थिरता के हित में इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए तथा अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।

हरमनप्रीत ने दिया झटकाः छोड़ी तीनों फॉर्मेट की कप्तानी

मुंबई, 06 अक्टूबर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने मंगलवार को भारतीय टीम की तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का एलान किया। हरमनप्रीत ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन अब वह बतौर खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहती हैं। हरमनप्रीत ने अपने संदेश में लिखा, 'आज मैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सभी फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ रही हूं। यह आसान फैसला नहीं है। इसमें वर्षों की यादें, भावनाएं, त्याग और ऐसे पल जुड़े हैं, जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे।'

37 वर्षीय हरमनप्रीत ने पांच टेस्ट, 51 वनडे और 155 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत की कप्तानी की है। कप्तान के रूप में उनका आखिरी काम पिछले महीने निशिन में भारतीय टीम को लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक दिलाना रहा।

हरमनप्रीत के कप्तानी छोड़ने का फैसला उस बैठक के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने भारतीय टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और मुख्य कोच अमोल मजूमदार के साथ बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया से मुलाकात की थी। गुवाहाटी में हुई इस बैठक में भारतीय महिला टीम के आगे के रोडमैप को लेकर चर्चा हुई थी।

हरमनप्रीत ने कहा कि उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट और टीम के लिए अपना सब कुछ दिया। कई मौकों पर उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन, विकास और निजी महत्वाकांक्षाओं को भी टीम के हित में पीछे रखा। उन्होंने लिखा, 'मैंने इस टीम और भारतीय महिला क्रिकेट को अपना खून, पसीना और समय दिया है। कई बार अपने खेल और निजी

महत्वाकांक्षाओं का एक हिस्सा भी पीछे रखा, क्योंकि मेरा मानना था कि टीम सबसे पहले है।' कप्तान के तौर पर लिए गए फैसलों को लेकर होने वाली आलोचनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। हरमनप्रीत ने कहा कि कई फैसले मुश्किल थे और हमेशा समझे नहीं गए, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य था- टीम को बेहतर बनाना और दूसरी खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका देना। हरमनप्रीत ने भारतीय टीम के साथ अपने सफर के उतार-चढ़ाव को याद किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने निराशा, दिल टूटने, आलोचना और मुश्किल दौर देखे, लेकिन इसके साथ जीत, जश्न और देश का प्रतिनिधित्व करने का गर्व भी महसूस किया। उन्होंने लिखा, 'मैंने सबसे बुरे दौर, दिल टूटने, आलोचना और संदेह देखे हैं। मैंने सबसे ऊंचे पल भी देखे हैं, जीत, जश्न और देश का प्रतिनिधित्व करने का गर्व।' विश्व कप जीत के बाद कप्तानी छोड़ने का उनका फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि वह अब टीम को सही दिशा में मान रही हैं। हरमनप्रीत ने कहा कि वह कप्तानी छोड़ते समय भावुक हैं, लेकिन उनके मन में शांति है। उन्हें भरोसा है कि भारतीय टीम के पास प्रतिभा, चरित्र और भविष्य के लिए मजबूत आधार मौजूद है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। मैंने इस टीम को अपना सब कुछ दिया। मैंने इस जिम्मेदारी को गर्व के साथ निभाया और भारतीय महिला क्रिकेट की अगुआई करने के विशेषाधिकार के लिए हमेशा आभारी रहूंगी।

देहरादून में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, बुजुर्ग दंपति समेत महिला पर पेचकस से हमला

देहरादून। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में मंगलवार को दिनदहाड़े एक तिहरे हत्याकांड में एक बदमाश ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग दंपति तथा उनके बचाव में आयी एक महिला की कथित तौर पर पेचकस से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, घटना दोपहर को तपोवन रोड पर विष्णुलोक कॉलोनी में हुई जहां आर्डिनेंस फैक्ट्री से सेवानिवृत्त हुए रमेश कपूर (80) और उनकी पत्नी रजनी कपूर (76) अकेले रहते थे। पुलिस के अनुसार रजनी कपूर पूर्व में अंग्रेजी की शिक्षिका थीं। वहीं इस घटना के बाद कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि इस घटना से पूरा प्रदेश दहल गया है और आम लोगों का पुलिस तथा राज्य सरकार से भरोसा डगमगा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बदमाश ने

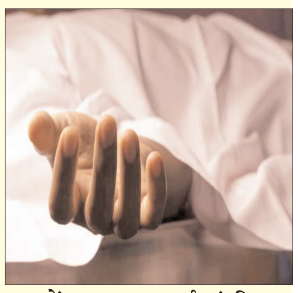

घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति पर कथित रूप से पेचकस से हमला करके उन्हें लहूलुहान कर दिया।

पुलिस के अनुसार उनकी चीखें सुनकर सामने के घर में काम करने वाली महिला शीला उनके घर पहुंची तो बदमाश ने उस भी हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक पड़ोसियों की मदद से घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां तीनों की मौत हो गयी। पुलिस ने बताया कि घटना की छानबीन शुरू कर दी गयी है।

सीएम मान के कैंप ऑफिस पर सीबीआई का छापा: ओएसडी के घर भी पहुंचे अधिकारी, मुख्यमंत्री बोले- भाजपा में घबराहट

चंडीगढ़, 06 अक्टूबर। सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी (विशेष ड्यूटी अधिकारी) राजबीर घुमम्न के संगरूर स्थित घर और उनके भाई के मोहाली स्थित घर पर छापेमारी की है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सीबीआई की टीम ने मोहाली के फेज-11 में गुरकिरपाल सिंह थिंद (ओएसडी राजबीर घुमम्न के भाई) के घर पर भी छापा मारा है। इसके साथ ही, सीबीआई की टीम मुख्यमंत्री कार्यालय में भी पहुंची हुई है।

सीबीआई के मुताबिक, आरोपियों पर अधिकारियों की पोस्टिंग में कथित तौर पर प्रभाव डालने और हेरफेर करने, विभागीय कार्रवाई, नीति निर्माण, प्रशासनिक मंजूरियों, टेंडर की शर्तों, लाइसेंसिंग, लैंड यूज कन्वर्जन, संपत्ति विवाद तथा राजस्व और भूमि से जुड़े मामलों में कथित तौर पर आर्थिक लाभ लेकर काम कराने के आरोपों की जांच की जा रही है।

जांच एजेंसी के अनुसार, मामले में यह आरोप भी है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने सरकार की ओर से आदेश और नीतियां जारी होने से पहले उनके ड्राफ्ट निजी व्यक्तियों तक पहुंचाए। सीबीआई ने राजबीर घुम्मन, नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और आरएस नागरा समेत अज्ञात सरकारी कर्मचारियों व निजी व्यक्तियों को मामले में नामजद किया है।

सीबीआई टीम ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में आरोपियों से जुड़े परिसरों पर पहुंची। एजेंसी ने तलाशी के दौरान मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों को जांच के लिए अपने कब्जे में लिया है। जब्त सामग्री में कथित रिश्वतखोरी और अनियमितताओं से जुड़े साक्ष्य तलाशे जा रहे हैं। सीएम मान ने सीबीआई की रेड को लेकर पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा ₹भाजपा ने पंजाब में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेरे कैंप ऑफिस में सीबीआई की रेड की गई है। अब पंजाब में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जाएगा, ताकि पंजाब

सरकार और मुझे बदनाम किया जा सके। लोगों से मिल रहे प्यार को देखकर भाजपा घबराहट में है।

सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बीते रोज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को ईडी की ओर से भेजे गए पत्रों की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। ईडी ने पंजाब के डीजीपी को तीन पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। पंजाब पुलिस के मामला दर्ज न किए जाने के बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनावई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे जिसके बाद ये रेड हुई है।

अरविंद केजरीवाल ने भी सीबीआई रेड पर प्रतिक्रिया देते हुए पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा चुनाव से दो माह पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय पर सीबीआई की रेड बीजेपी कि बौखलाहट का नतीजा है। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है।

DAKS REHAB CENTRE
(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)
Contact us: 9820519851
विल्डिंग नंबर 3, प्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीबी नगर मुंबई-37

* Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
* बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
* वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
* DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
* NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
* चिकित्सा उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
* एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
* पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
* मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
* विशेषज्ञ डॉक्टरो से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
* मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तीयों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध

बेहतर विकल्प एवं जरूरी मुद्दों का अभाव ही विपक्ष की अक्षमता

-ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि यहां कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती और कोई भी विपक्ष हमेशा के लिए विपक्ष नहीं रहता। सत्ता के लंबे कार्यकाल के बाद स्वाभाविक रूप से सरकार के प्रति उकताहट पैदा होती है। लेकिन उकताहट और सत्ता परिवर्तन के बीच एक बड़ा अंतर है। मतदाता किसी सरकार से नाराज हो सकता है, उसके कामकाज पर सवाल उठा सकता है, फिर भी केवल नाराजगी के आधार पर किसी ऐसे विकल्प को स्वीकार नहीं करता, जिसके पास देश के भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा न हो, जो सत्ता का लालची एवं बेहतर विकल्प से वंचित हो। आज भारतीय राजनीति में विपक्ष के सामने मूल प्रश्न यही है-क्या वह केवल सरकार से असंतुष्ट है या जनता के सामने कोई विश्वसनीय विकल्प भी रख रहा है? राहुल गांधी लंबे समय से यह सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार के प्रति अपेक्षित एंटी-इंकंबेंसी दिखाई क्यों नहीं देती। उनका आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी और ह्यवोट चोरीह्ल के कारण जनता की वास्तविक इच्छा सामने नहीं आ पा रही। इन आरोपों के समर्थन में उनके द्वारा प्रस्तुत दावों को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस जारी है, उन्हें अंतिम रूप से सिद्ध तथ्य मानना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता पर उठने वाले प्रत्येक प्रश्न का निष्पक्ष और तथ्यात्मक उत्तर मिलना लोकतंत्र के हित में है।

इसी संदर्भ में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विवाद महत्वपूर्ण हो गया है। निर्वाचन आयोग स्वयं एसआईआर-2026 से संबंधित मतदाता सेवाएं और मतदाता सूची उपलब्ध करा रहा है तथा वह अपने को स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण बताता है। दूसरी ओर विपक्ष ने इस प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस विवाद को अब सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती मिली है। इस पूरे मामले का अंतिम निष्कर्ष राजनीतिक नारों से नहीं, संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया से निकलेगा। यहीं विपक्ष की राजनीति की असली परीक्षा शुरू होती है। चुनाव आयोग के विरुद्ध आंदोलन करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। मतदाता सूची में यदि किसी पात्र नागरिक का नाम गलत ढंग से हटाया गया है तो उसका विरोध होना चाहिए। यदि किसी अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र की रक्षा केवल आयोग के विरोध से नहीं होगी। लोकतंत्र की रक्षा तब होगी जब विपक्ष जनता को यह भी बताए कि सत्ता मिलने पर वह शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शहरी जीवन, कानून-व्यवस्था और प्रशासन में क्या बदलेगा।

यही वह बिंदु है जहां ह्यवोट चोरीह्ल का राजनीतिक विमर्श जनता के रोजमर्रा के सवालों से टकराता है। एक सामान्य परिवार को बच्चों की महंगी शिक्षा की चिंता है। रोजगार की बदलती प्रकृति, एआई और नई तकनीक के कारण पारंपरिक कौशल तेजी से अप्रासंगिक हो रहे हैं। डिग्री लेने के बाद भी रोजगार की गारंटी नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की घटनाएं युवाओं के विश्वास को चोट पहुंचाती हैं। ऐसे में युवा यह जानना चाहता है कि अगली सरकार परीक्षा व्यवस्था को कैसे विश्वसनीय बनाएगी, स्कूलों की गुणवत्ता कैसे सुधारेगी और बदलती तकनीकी अर्थव्यवस्था के लिए करोड़ों युवाओं को तैयार कैसे करेगी। किसान की समस्या भी केवल एमएसपी या आंदोलन तक सीमित नहीं है। फसल आने पर कीमत गिर जाती है और कुछ महीने बाद वही प्याज, टमाटर या दूसरी सब्जियां महंगी हो जाती हैं। इसका समाधान केवल विरोध में नहीं, बल्कि गांव-कस्बे तक भंडारण, कोल्ड-चेन, प्रसंस्करण, कृषि बाजार और मूल्यवर्धन की मजबूत व्यवस्था में है। विपक्ष यदि कृषि सुधारों का विरोध करता है तो उसे यह भी बताना होगा कि वह वैकल्पिक कृषि ढांचा किस तरह खड़ा करेगा।

रोजगार का प्रश्न इससे भी बड़ा है। भारत की युवा आबादी को उद्योग, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, अनुसंधान और नई तकनीक से जोड़ना होगा। निवेश के लिए स्थिर कानून-व्यवस्था, पारदर्शी प्रशासन और भरोसेमंद कारोबारी वातावरण जरूरी है। केवल बड़े उद्योगपतियों पर राजनीतिक प्रहार या संपत्ति की गणना जैसे नारों से रोजगार पैदा नहीं होते। विपक्ष यदि संपत्ति के पुनर्वितरण या सामाजिक न्याय की बात करता है तो उसे साथ ही यह भी बताना होगा कि संपत्ति और अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे। ह्यजितनी आबादी, उतना हकह्ल जैसी राजनीति सामाजिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न को सामने लाती है, लेकिन आज की चुनौती प्रतिनिधित्व के साथ-साथ क्षमता निर्माण की भी है। पिछड़े, दलित, आदिवासी और कमजोर वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और अवसर मिलें-यह सामाजिक न्याय का अधिक स्थायी आधार है। केवल आंकड़े गिनना पर्याप्त नहीं, उन आंकड़ों के पीछे खड़े मनुष्य का जीवन बदलना जरूरी है। इस पूरे परिदृश्य में ममता बनर्जी की भूमिका विशेष चर्चा का विषय बनी है। राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर नया विमर्श अवश्य उभरा है। हाल की इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्होंने विपक्ष का दायरा बढ़ाने और व्यापक एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा संकट केवल भाजपा से मुकाबला नहीं, बल्कि उसके भीतर का परस्पर अविश्वास है। सीटों का बंटवारा, क्षेत्रीय वर्चस्व, नेतृत्व का प्रश्न और राज्यों में एक-दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का राष्ट्रीय स्तर पर साथ आना आसान नहीं है। आज की स्थिति में आप का चुनाव आयोग तक प्रस्तावित मार्च से अलग रहकर अपना रास्ता अपनाना भी इस अंतर्विरोध को दिखाता है।

कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी, वामपंथी दल, राजद, आप और दूसरे क्षेत्रीय दल जब अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग राजनीति करते हैं, तब राष्ट्रीय मंच पर उनका साझा न्यूनतम कार्यक्रम क्या है? जनता इसी का उत्तर चाहती है। चुनाव आयोग के मुद्दे पर भी यही कसौटी लागू होती है। इंडिया गठबंधन ने 6 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग तक मार्च सहित विरोध कार्यक्रम घोषित किए हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई है। यह आंदोलन संवैधानिक प्रश्नों को सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला सकता है। लेकिन यदि विपक्ष का पूरा राजनीतिक अभियान केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे तक सीमित रह गया, तो इससे चुनावी संस्थाओं पर व्यापक विश्वास का प्रश्न हल नहीं होगा। उसे यह भी बताना होगा कि सत्ता में आने पर निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, मतदाता सूची, ईवीएम-वीवीपैट, चुनावी चंदे और चुनावी पारदर्शिता को लेकर वह कौन से संस्थागत सुधार करेगा।

बड़ा प्रश्न है कि सत्ता की पात्रता को विकसित करने के लिये विपक्ष क्यों नहीं जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सकारात्मक राजनीति को बल देती। वास्तव में विपक्ष के सामने सबसे बड़ा संकट मुद्दों की कमी नहीं, मुद्दों को समाधान में बदलने की क्षमता का है। बेरोजगारी है, शिक्षा का संकट है, कृषि की समस्या है, स्वास्थ्य का खर्च है, महंगाई की चिंता है, शहरी प्रदूषण है, एआई से बदलती नौकरियां हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है। जनता इन सबको प्रतिदिन महसूस करती है। लेकिन राजनीतिक विमर्श बार-बार मोदी बनाम कौन, राहुल बनाम मोदी, ईवीएम बनाम बैलेट और आयोग बनाम विपक्ष की बहस में सिमट जाता है। भारतीय मतदाता सरकार से मोहभंग होने पर भी यह देखता है कि उसके सामने विकल्प क्या है। वह जमीन छोड़कर अंधे कुएं में छलांग नहीं लगाता। उसे ऐसा विपक्ष चाहिए जो सरकार की कमियां गिनाने के साथ अपनी क्षमताएं भी बताए, जो केवल सत्ता की आलोचना नहीं, शासन का वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करे, जो चुनाव आयोग से सवाल पूछे तो अपनी चुनावी पारदर्शिता की कसौटी भी सामने रखे, जो सामाजिक न्याय की बात करे तो शिक्षा और अवसर का रास्ता भी बताए, जो उद्योगपतियों से सवाल करे तो निवेश और रोजगार की अपनी नीति भी स्पष्ट करे।

लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही जितनी जरूरी है, विपक्ष की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। सत्ता से मोहभंग लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उस मोहभंग को राजनीतिक परिवर्तन में बदलने के लिए विश्वसनीय विकल्प चाहिए। आज इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती भाजपा और नरेंद्र मोदी से लड़ने से बड़ी है-उसे जनता के मन में यह विश्वास पैदा करना है कि उसके पास भारत के अगले दशक की कोई स्पष्ट, ठोस और क्रियान्वित करने योग्य कहानी भी है। विपक्ष यदि यह विश्वास पैदा कर पाया तो चुनाव आयोग का मुद्दा भी लोकतांत्रिक सुधार की सार्थक बहस बनेगा, ममता बनर्जी की भूमिका भी सार्थक होगी और राहुल गांधी के सवाल भी व्यापक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनेंगे।

मजबूरी का राजनीतिक व्याकरणः चंद्रशेखर की चुनौती और आकाश

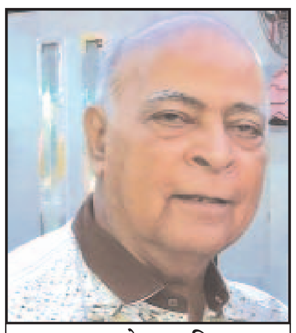

अशोक भाटिया

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती द्वारा अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त करना भारतीय राजनीति की समकालीन बिसात पर एक ऐसा कदम है, जिसे समझने के लिए केवल तात्कालिक घटनाओं को देखना पर्याप्त नहीं होगा। अक्टूबर 2026 की यह सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल न केवल बीएसपी के भीतर चल रहे गहरे अंतर्विरोधों को रेखांकित करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि दलित राजनीति का यह ऐतिहासिक दुर्ग इस समय अपने अस्तित्व के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। उत्तराधिकार की इस खींचतान और मात्र 25 दिनों के भीतर निष्कासन से लेकर पुनः ताजपोशी तक का यह नाटकीय घटनाक्रम एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है: क्या मायावती के फैसले किसी सोची-समझी दूरगामी रणनीति का हिस्सा हैं, या फिर यह जमीनी हकीकत से उपजी एक ऐसी सियासी मजबूरी है जिसे अब और नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया था? राजनीति में 'यू-टर्न' या अपनी ही चालों को पलटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से पिछले तीन वर्षों में आकाश आनंद के राजनीतिक जीवन में उतार-चढ़ाव आए हैं, वह अभूतपूर्व है। दिसंबर 2023 में उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया जाना, मई 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच आक्रामक भाषा का हवाला देकर 'अपरिपक्व' घोषित कर हटा दिया जाना, फिर जून में वापसी, मार्च-मई 2025 में फिर निष्कासन, और फिर सितंबर 2026 में ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव का तर्क देकर 'पूर्णतः मुक्त' कर देना–यह पूरी क्रोनोलॉजी दर्शाती है कि बीएसपी का सांगठनिक ढांचा इस समय एक गंभीर दुविधा के दौर से गुजर रहा है। आइए इस सम्पादकीय के माध्यम से उन गहरे राजनीतिक, सामाजिक और सांगठनिक कारणों का विश्लेषण करें कि आखिर मायावती को अपनी ही गोटियां बार-बार क्यों बदलनी पड़ रही हैं।

दरअसल कांशीराम ने जब बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी थी, तो उनका मूल ध्येय एक सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक शक्ति में बदलना था। उन्होंने 'बहुजन' समाज को शासक वर्ग बनाने का सपना देखा था। लेकिन समय के साथ, विशेष रूप से पिछले एक दशक में, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी एक काडर-आधारित वैचारिक आंदोलन से सिमटकर एकल नेतृत्व वाली पार्टी बन गई है। मायावती के राजनीतिक दर्शन का एक सबसे बड़ा नियम रहा है–पूर्ण और निर्विवाद नियंत्रण। पार्टी के भीतर कोई दूसरा पावर सेंटर बीएसपी की कार्यशैली में कभी बर्दाश्त नहीं किया गया। आकाश आनंद की बार-बार की बेदखली और वापसी के पीछे इस 'कंट्रोल' की भावना को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सितंबर 2026 में जब आकाश को हटाया गया, तो मायावती ने सीधे तौर पर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ पर आरोप लगाया कि आकाश उनके प्रभाव में आकर स्वायत्त फैसले ले रहे थे। मायावती के लिए पार्टी और आंदोलन से बड़ा कोई परिवार नहीं हो सकता। जैसे ही अशोक सिद्धार्थ ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा की और 2 अक्टूबर को आकाश ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से आत्मसमर्पण और माफी का मार्ग चुना, वैसे ही उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया। यह दर्शाता है कि मायावती पार्टी के शीर्ष पर

हिन्दी दैनिक
उत्तरशक्ति
मार्गदर्शन

किसी भी प्रकार के 'रिमोट कंट्रोल' या बाहरी प्रभाव को स्वीकार नहीं कर सकतीं, भले ही वह उनके ससुर या अन्य कोई संबंधी ही क्यों न हो। गोटियां बदलने की यह प्रक्रिया असल में पार्टी पर अपनी पूर्ण सत्ता को अक्षुण्ण रखने का एक सचेत प्रयास है।

मायावती के इस ताजा यू-टर्न के पीछे सबसे बड़ी सियासी मजबूरी सोशल इंजीनियरिंग और युवा वोट बैंक की है। बीएसपी का पारंपरिक कोर वोटर (विशेषकर जाटव समाज) दशकों से पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों के आंकड़े गवाही देते हैं कि यह आधार धीरे-धीरे खिसक रहा है। आज का दलित युवा 1990 के दशक के राजनीतिक संघर्षों से भावनात्मक रूप से उस तरह नहीं जुड़ा है जैसे उनके माता-पिता जुड़े थे। उसे रोजगार, पेपर लीक, आरक्षण की समीक्षा और सड़क पर उतरकर संघर्ष करने वाला आक्रामक नेतृत्व चाहिए। इस शून्यता को भरने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आजाद 'रावण' जैसे युवा नेता उभरे हैं, जो सीधे तौर पर बीएसपी के काडर में सेंध लगा रहे हैं। जब आकाश आनंद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में आक्रामक भाषण दिए और सीधे तौर पर सत्तापक्ष को कटघरे में खड़ा किया, तो बीएसपी के बिखरे और हताश हो रहे युवा काडर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। मायावती को यह भली-भांति अहसास हो गया है कि यदि आकाश आनंद को लंबे समय तक हाशिए पर रखा गया, तो पार्टी का बचा-खुचा युवा कार्यकर्ता पूरी तरह से दूसरे विकल्पों की ओर रुख कर लेगा। आकाश को वापस लाना किसी रणनीति से ज्यादा बीएसपी के अस्तित्व को बचाने की एक अनिवार्य सांगठनिक मजबूरी बन चुका था।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय बेहद संवेदनशील मोड़ पर है। वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीएसपी के भविष्य के लिए 'करो या मरो' की लड़ाई की तरह हैं। वर्तमान में पार्टी के पास न तो लोकसभा में कोई उल्लेखनीय उपस्थिति है और न ही राज्य विधानसभा में वैसी ताकत बची है जैसी 2007 के बहुमत के दिनों में हुआ करती थी। ऐसे में चुनाव से ठीक एक साल पहले पार्टी के भीतर निरंतर सांगठनिक फेरबदल और असमंजस की स्थिति बीएसपी को रेस से पूरी तरह बाहर कर सकती थी।

मायावती ने आकाश आनंद की नियुक्ति के समय खुद यह उम्मीद जताई है कि अब बार-बार सांगठनिक बदलाव नहीं करने पड़ेंगे और चुनावी तैयारियां सुचारू रूप से चल सकेंगी। आकाश आनंद को कमान सौंपकर मायावती एक तीर से दो निशाने साध रही हैं: पहली बात, वह खुद को चुनावी रणनीति, टिकटों के बंटवारे और बड़े नीतिगत फैसलों तक सीमित रख सकती हैं दूसरी बात, धूप और धूल भरी जमीनी रैलियों, युवाओं के बीच जनसंपर्क और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एक ऊर्जावान युवा चेहरे को दी जा सकती है, जिसकी भाषा आज के युवाओं को समझ आती है। मायावती ने अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया कि पार्टी के अधिकांश वरिष्ठ नेताओं, प्रभारियों और जमीनी कार्यकर्ताओं का यह पुरजोर दबाव था कि आकाश आनंद को वापस लाया जाए। जब आकाश को हटाया गया था, तो उनके छोटे भाई ईशान आनंद को कुछ राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद पुत्री दीपिका आनंद को भी आगे लाने की चर्चाएं उठीं। लेकिन सांगठनिक रूप से बीएसपी के भीतर यह संदेश जा रहा था कि पार्टी बिना किसी स्पष्ट विजन और स्थिर नेतृत्व के एक पारिवारिक प्रयोगशाला बन गई है। ईशान आनंद और आनंद कुमार (आकाश के पिता) ने भी इस बात पर सहमति जताई है कि नेतृत्व के लिए आकाश ही सबसे उपयुक्त चेहरा हैं। पार्टी के भीतर पैदा हो रही इस सांगठनिक शून्यता और भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए मायावती को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। गोटियां बदलने की उनकी यह आदत असल में उनके प्रयोगों की विफलता को भी दर्शाती है; जब उन्हें लगता है कि उनका कोई प्रयोग पार्टी को कमजोर कर रहा है, तो वह तुरंत एक बड़ा यू-टर्न लेकर पुरानी स्थिति को बहाल कर देती हैं ताकि नुकसान को कम किया जा सके।

वैसे भी मायावती की राजनीति हमेशा से चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती रही है। चाहे वह 1995 का ऐतिहासिक गठबंधन और उसकी परिणति हो, या फिर 2007 का 'सोशल इंजीनियरिंग' का वह ऐतिहासिक प्रयोग जिसने उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार दी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। आज बीएसपी एक गहरे अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। आकाश आनंद की यह पुनर्नियुक्ति मायावती की कोई स्वेच्छा से चुनी गई रणनीति नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक परिवेश में पार्टी को बिखरने से बचाने की एक अपरिहार्य सियासी विवशता है। आकाश के सामने अब चुनौती सिर्फ अपनी बुआ की उम्मीदों पर खरा उतरने की नहीं है, बल्कि उनके सामने चुनौती उस 'बहुजन आंदोलन' को पुनर्जीवित करने की है जो कभी उत्तर भारत की राजनीति की दिशा तय करता था। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती का यह यू-टर्न 2027 में पार्टी के लिए संजीवनी बूटी साबित होता है, या फिर यह निरंतर गिरते ग्राफ को रोकने का एक और अस्थायी प्रयास बनकर रह जाएगा।

विपक्ष के हमलों के सामने भाजपा का कमजोर काउंटर अटैक

भारतीय राजनीति के फलक पर विपक्ष इस समय पूरी तरह से आक्रामक और सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। राफेल डील से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन(एसआईआर) जैसे मुद्दों पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छेड़ रखा है। इस आक्रामक घेरेबंदी के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का वह पारंपरिक काउंटर अटैक दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी जानी जाती है। जबकि विपक्ष लगातार मुद्दे बदल कर हमलावर है। विपक्ष का एजेंडा और रणनीति लगातार बदल रही है। कुछ समय पहले तक जो विपक्ष सिर्फ संसद के भीतर विरोध दर्ज कराता था, वह अब अदालतों, स्वतंत्र मंचों और अंतरराष्ट्रीय कड़ियों को जोड़कर सरकार को घेर रहा है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, उसने सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलने का काम किया है। 06 अक्टूबर को भी इंडी गठबंधन ने सीईसी के खिलाफ सड़क पर खूब संग्राम किया, जवाब में भाजपा के बड़े नेता जैसे कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान या पार्टी प्रवक्ता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के इस अभियान को भ्रामक और अराजकता फैलाने वाला करार देने तक ही सीमित नजर आयें। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका सांगठनिक ढांचा और जमीनी कार्यकर्ता माने जाते रहे हैं। लेकिन मौजूदा दौर के इस राजनीतिक हो-हल्ले में भाजपा के पार्षद, विधायक और सांसद जैसे जनप्रतिनिधि अपने नेतृत्व के पक्ष में मुखरता से खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। संसद और मीडिया में गिने-चुने प्रवक्ताओं को छोड़ दें, तो जमीन पर सांसदों और विधायकों का कोई बड़ा समूह विपक्ष के इन तथाकथित फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए जनता के बीच जाता नहीं दिख रहा है। चाहे वह परीक्षाओं की प्रणाली को लेकर विपक्ष का घेराव हो या फिर चुनाव सुधारों पर फैलाया जा रहा भ्रम, भाजपा के स्थानीय नेता अपनी ही सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का बचाव करने में हिचकिचाते नजर आ रहे हैं। इस खामोशी ने जनता के एक बड़े वर्ग में यह संदेश दिया है कि विपक्ष के आरोपों का ठोस जवाब देने में पार्टी का जमीनी

-अजय कुमार

कैडर असमर्थ महसूस कर रहा है,जबकि विपक्ष अब केवल राजनीतिक रैलियों तक सीमित नहीं है; उसने अदालतों को अपना मुख्य रणनीतिक केंद्र बना लिया है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता से लेकर सरकार की प्रशासनिक नीतियों तक, हर संवेदनशील मुद्दे को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। ऐसे समय में भाजपा के कानूनी सलाहकारों और कानूनविदों की टीम मीडिया या सार्वजनिक फोरम पर उस तार्किकता और आक्रामकता के साथ खड़ी नहीं दिखती, जिसकी जरूरत है। अदालती फैसलों या चल रही बहसों का सरलीकृत रूप जनता के सामने रखने में भाजपा का कानूनी विंग पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रहा है। जब विपक्ष के वकील अदालतों के बाहर मीडिया कैमरों के सामने एकतरफा नैरेटिव सेट कर रहे होते हैं, तब भाजपा की तरफ से उस कानूनी बारीकी को जनता की भाषा में समझाने वाला कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता। भाजपा का मीडिया और आईटी सेल कभी विरोधी दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हुआ करता था। हाल ही में संगठन के भीतर कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें अमित मालवीय के लंबे कार्यकाल के बाद दीपक म्हास्के को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी सौंपी गई और संगठन में राम माधव व स्मृति ईरानी जैसे वरिष्ठ नेताओं की वापसी हुई। इसके बावजूद, बदली हुई सोशल मीडिया टीम विपक्ष की नई और सुव्यवस्थित डिजिटल सेना के सामने हल्की और अप्रभावी साबित हो रही है। भाजपा का सोशल मीडिया कंटेंट अब विकासात्मक मील के पत्थरों और आर्थिक आंकड़ों की उबाऊ प्रस्तुति तक सिमट कर रह गया है, जबकि विपक्ष सीधे युवाओं के गुस्से, बेरोजगारी और प्रशासनिक कमियों को भावनात्मक रूप से भुनाने में जुटा है। भाजपा का मीडिया सेल केवल रोजमर्रा की तू-तू मैं-मैं में उलझा हुआ है, जिससे वह धार गायब हो चुकी है जो कभी विरोधियों के नैरेटिव को चंद घंटों में जमींदोज कर देती थी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी हमेशा अप्रत्याशित और विनाशकारी काउंटर-अटैक के लिए जानी जाती रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुशासन के जरिए विपक्ष के झूठे नैरेटिव को बेअसर किया है, लेकिन संगठन के स्तर पर यह असर फीका पड़ रहा है। उधर, मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने में विदेशी शक्तियों और बाहरी तत्वों के शामिल होने के आरोपों पर भी भारतीय राजनीति में तीखी बहस जारी है। सत्ता पक्ष और सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि भारत की संप्रभुता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सरकार की छवि को वैश्विक स्तर पर प्रभावित करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, विपक्ष इन दावों को घरेलू विफलताओं से ध्यान भटकाने का एक जरिया बताता है। विदेशी जमीन से संचालित डिजिटल इकोसिस्टम पर सत्तारूढ़ दल भाजपा ने आधिकारिक तौर पर आरोप लगाया है कि देश के भीतर सरकार विरोधी एजेंडा और वोट चोरी जैसे नैरेटिव को हवा देने वाले कई सोशल मीडिया हैंडल भारत से नहीं, बल्कि विदेशी धरती से संचालित हो रहे हैं। भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा सार्वजनिक किए गए विवरणों के अनुसार, कांग्रेस और उसके सहयोगी तंत्र से जुड़े कुछ प्रमुख सोशल मीडिया हैंडल और इन्फ्लुएंसर्स के नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और थाईलैंड जैसी विदेशी लोकेशंस से जुड़े पाए गए हैं। पार्टी का दावा है कि यह भारत में असंतोष भड़काने के लिए एक व्यवस्थित विदेशी नेटवर्क का हिस्सा है।भारत में बड़े आंदोलनों (जैसे छात्र प्रदर्शन या किसान आंदोलन) के दौरान विदेशी टूलकिट की सक्रियता के प्रमाण मिले हैं। सुरक्षा बलों और साइबर सेल की जांच रिपोर्टों के अनुसार, हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तान स्थित हैंडलों से संचालित होने वाले फेक न्यूज टूलकिट्स सक्रिय पाए गए हैं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा जनित और हेरफेर किए गए वीडियो का उपयोग कर युवाओं को सरकार और रक्षा बलों के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया गया। इससे पहले, ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में भी खालिस्तानी संगठनों और विदेशी कड़ियों (जैसे कनाडा स्थित पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन) के शामिल होने के आरोप लगे थे। भाजपा के आईटी सेल ने इसे रेखांकित करते हुए आरोप लगाया कि विदेशी ताकतें भारत में एक कमजोर गठबंधन सरकार स्थापित करने के लिए वित्तीय और रणनीतिक प्रयास कर रही थीं।

समाज की जरूरतें बढ़ीं, सुविधाएं कम पड़ गईं

समय बदल रहा है। जीवन जीने के तौर-तरीके बदल रहे हैं। तकनीक ने दुनिया को हमारी हथेली में ला दिया है। घर बैठे बैंकिंग, खरीदारी, शिक्षा, सरकारी सेवाएं और संवाद की सुविधाएं उपलब्ध हैं। शहरों में चौड़ी सड़कें, बड़े अस्पताल, आधुनिक विद्यालय, मेट्रो और डिजिटल व्यवस्था विकास की नई तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। देश भी अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक दूसरा भारत भी है–वह भारत जो आज भी महंगाई से जूझ रहा है, रोजगार की तलाश में भटक रहा है, इलाज के खर्च से चिंतित है, बच्चों की शिक्षा का बोझ उठा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और बुजुर्गों के अकेलेपन से परेशान है। प्रश्न यह नहीं है कि देश में विकास हुआ या नहीं। प्रश्न यह है कि इस विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंचा? यही सवाल आज हमारे सामने सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती बनकर खड़ा है। विकास हो, लेकिन जीवन भी आसान हो विकास का अर्थ केवल नई परियोजनाएं, नई इमारतें और आधुनिक तकनीक नहीं हो सकता। विकास तब सार्थक है जब सामान्य नागरिक के जीवन में कठिनाइयां कम हों। यदि सड़क बन गई लेकिन उस पर सुरक्षा नहीं है, अस्पताल बन गया लेकिन गरीब के लिए इलाज महंगा है, विद्यालय है लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, रोजगार योजनाएं हैं लेकिन युवाओं को अवसर नहीं मिलते, डिजिटल व्यवस्था है लेकिन बुजुर्ग और अशिक्षित व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर पाता–तो हमें विकास की दिशा पर विचार करना ही होगा। व्यवस्था की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण वह व्यक्ति होना चाहिए जो सबसे कमजोर स्थिति में खड़ा है। महंगाई ने घर की खुशियों को किया प्रभावित महंगाई का असर केवल बाजार में दिखाई नहीं देता। उसका सबसे बड़ा प्रभाव घर की रसोई में दिखाई देता है। मध्यमवर्गीय परिवार अपनी आय और खर्च के बीच लगातार संतुलन बनाने की कोशिश करता है। भोजन, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई, मकान का किराया या किस्त, बिजली, पानी, यात्रा, दवाइयां और अन्य आवश्यकताओं का खर्च परिवार के बजट पर लगातार दबाव डालता है। कम आय वाले परिवार के लिए तो स्थिति और कठिन है। वहां जरूरत और सामर्थ्य के बीच दूरी बढ़ती जाती है। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रभावी निगरानी, जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण तथा कमजोर वर्गों के लिए लक्षित सहायता व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। भूखे पेट विकास का आंकड़ा संतोष नहीं दे सकता। रोजगार चाहिए, केवल आश्वासन नहीं देश का युवा ऊर्जा, प्रतिभा और सपनों से भरा हुआ है। वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। वह अपने माता-पिता का सहारा बनना चाहता है। लेकिन रोजगार का प्रश्न आज भी गंभीर है। युवाओं को केवल सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा में नहीं रखना चाहिए। रोजगार के नए क्षेत्र विकसित करने होंगे। छोटे उद्योग, स्थानीय कारोबार, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन, हस्तशिल्प, डिजिटल सेवाएं और कौशल आधारित रोजगार को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन देना होगा। गांव का युवा रोजगार के लिए मजबूरी में शहर की ओर पलायन न करे, इसके लिए गांवों में ही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना आवश्यक है। जिस हाथ में हुनर है, उस हाथ को काम मिलना चाहिए। शिक्षा–व्यवसाय नहीं, भविष्य का निर्माण शिक्षा समाज की रीढ़ है। लेकिन शिक्षा का बढ़ता खर्च अनेक परिवारों के सामने गंभीर चुनौती है। आज माता-पिता अपने

-विक्रम दयाल

बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अपनी आवश्यकताओं में कटौती करते हैं। निजी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तकनीकी शिक्षा और अन्य शैक्षणिक खर्च सामान्य परिवार की आर्थिक क्षमता पर भारी पड़ सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि सरकारी विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को इतना मजबूत किया जाए कि हर बच्चे को अपनी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना अच्छी शिक्षा मिल सके। शिक्षा में तकनीक आए, आधुनिकता आए, लेकिन मानवीयता और संस्कार पीछे न छूटें। स्वास्थ्य व्यवस्था आम आदमी के लिए हो किसी परिवार के लिए बीमारी केवल स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती, वह आर्थिक संकट भी बन सकती है। एक गंभीर बीमारी परिवार की वर्षों की बचत समाप्त कर सकती है। गरीब और निम्न-मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह संकट और गहरा होता है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक, दवाइयां, जांच और विशेषज्ञ सेवाएं पर्याप्त हों। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हों। मरीज को छोटी-सी जांच या उपचार के लिए बड़े शहर की ओर भागना न पड़े। स्वास्थ्य सुविधा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मरीज को यह भय न सताए कि इलाज कराऊंगा तो घर कैसे चलाऊंगा। महिला सुरक्षा–समाज की असली परीक्षा महिला सुरक्षा का विषय केवल अपराध की घटना के बाद चर्चा करने का विषय नहीं होना चाहिए। यह सामाजिक संस्कार और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों का प्रश्न है। महिलाओं को घर से बाहर निकलते समय भय न हो। कार्यस्थल पर सम्मान मिले। सार्वजनिक परिवहन सुरक्षित हो। शिकायत की स्थिति में तत्काल सहायता मिले और अपराधी को कानून के अनुसार कठोर दंड मिले। इसके साथ परिवारों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। बेटियों को सुरक्षा के नाम पर सीमित करने के बजाय समाज के वातावरण को सुरक्षित बनाना होगा। बेटी को बंद दरवाजे नहीं, सुरक्षित समाज चाहिए। बुजुर्गों की चिंता कौन करेगा? आधुनिक जीवन की व्यस्तता ने परिवार की संरचना को भी प्रभावित किया है। संयुक्त परिवारों का स्थान धीरे-धीरे छोटे परिवार लेते जा रहे हैं। ऐसे में बुजुर्गों के सामने अकेलापन एक बड़ी समस्या बन रहा है। जिस पीढ़ी ने अपने बच्चों को पढ़ाया, घर बनाया और परिवार को संभाला, उसे जीवन के अंतिम पड़ाव पर उपेक्षा का अनुभव नहीं होना चाहिए। बुजुर्गों को केवल पेंशन या आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें बातचीत चाहिए, सम्मान चाहिए और यह भरोसा चाहिए कि परिवार और समाज में उनका महत्व आज भी बना हुआ है। गांवों को केवल वोट का क्षेत्र न समझा जाए भारत की आत्मा गांवों में बसती है–यह बात हम वर्षों से सुनते आए हैं। लेकिन गांवों में रहने वाले लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को निरंतर प्राथमिकता देना भी उतना ही जरूरी है। सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंटरनेट, सिंचाई, कृषि बाजार और रोजगार जैसी सुविधाएं गांवों में मजबूत हों तो ग्रामीण पलायन कम हो सकता है। किसान केवल उत्पादन करने वाला व्यक्ति नहीं है। वह देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। उसकी आय, लागत और बाजार से जुड़े प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। शहरों की चमक और बढ़ती परेशानियां शहर अवसर देते हैं, लेकिन शहरों की अपनी समस्याएं भी हैं। बढ़ती आबादी, यातायात, प्रदूषण, महंगा आवास, पानी की समस्या और सार्वजनिक सेवाओं पर बढ़ता दबाव आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है। शहरों का विकास केवल ऊंची इमारतों से नहीं होना चाहिए। नागरिकों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, हरियाली, सुरक्षित परिवहन, पर्याप्त सार्वजनिक स्थान और बेहतर नागरिक सुविधाएं भी चाहिए। स्मार्ट शहर वही है जहां नागरिक का जीवन सचमुच सरल हो। डिजिटल सुविधा के साथ डिजिटल संवेदना भी तकनीक ने बहुत कुछ आसान किया है। लेकिन हर व्यक्ति तकनीक के साथ समान गति से नहीं चल सकता। बुजुर्ग, ग्रामीण, अशिक्षित और तकनीकी रूप से कमजोर नागरिकों को डिजिटल व्यवस्था में सहायता की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं समझ पाता तो उसे व्यवस्था से बाहर नहीं किया जा सकता। डिजिटल भारत का उद्देश्य यह होना चाहिए कि तकनीक नागरिक को सुविधा दे, परेशानी नहीं। सुविधाओं से अधिक जरूरी है जवाबदेही सरकारें योजनाएं बनाती हैं। बजट तय होते हैं। घोषणाएं होती हैं। लेकिन किसी योजना की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब उसका लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके लिए वह बनाई गई है। कागज पर बनी योजना और जमीन पर दिखाई देने वाली योजना के बीच का अंतर समाप्त करना होगा। इसके लिए प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता आवश्यक है। जनता को अपनी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो। व्यवस्था में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि नागरिक की आवाज सुनी जाएगी। समाज में संवाद क्यों घट रहा है? हमारे पास संवाद के साधन पहले से अधिक हैं, लेकिन मनुष्य के बीच संवाद कम होता जा रहा है। मोबाइल पर संदेशों की भरमार है, मगर परिवार में बैठकर बात करने का समय कम है। सोशल मीडिया पर हजारों मित्र हैं, मगर जरूरत के समय साथ खड़े होने वाले लोगों की संख्या कभी-कभी बहुत कम दिखाई देती है। समाज की अनेक समस्याओं की जड़ में संवाद का अभाव भी है। परिवार में संवाद हो, पीढ़ियों में संवाद हो, समाज और प्रशासन में संवाद हो। असहमति हो सकती है, लेकिन संवाद बंद नहीं होना चाहिए। केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी समाज से हम बहुत कुछ चाहते हैं, सरकार से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमें स्वयं भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। सड़क साफ रखना केवल नगर निकाय की जिम्मेदारी नहीं। यातायात नियमों का पालन करना केवल पुलिस का काम नहीं। महिलाओं का सम्मान केवल कानून का विषय नहीं। बुजुर्गों की देखभाल केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं। एक अच्छा समाज सरकार और जनता दोनों की साझी जिम्मेदारी से बनता है। जरूरतों का समाज, संवेदनाओं का राष्ट्र आज समाज को केवल सुविधाओं की सूची नहीं चाहिए। उसे ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें सुविधा के साथ सम्मान हो, कानून के साथ न्याय हो, विकास के साथ रोजगार हो, शिक्षा के साथ संस्कार हों और तकनीक के साथ संवेदना हो। हमें यह तय करना होगा कि विकास की दौड़ में कोई पीछे न छूटे। किसी गरीब की थाली खाली न रहे। किसी युवा की प्रतिभा बेरोजगारी में न दबे। किसी बेटी को भय में जीवन न बिताना पड़े। किसी बुजुर्ग को अपने ही घर में अकेलापन महसूस हो।,किसी मरीज को पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न होना पड़े। और किसी नागरिक को अपनी जायज समस्या के समाधान के लिए दर-दर भटकना न पड़ेयही वास्तविक जनकल्याण है। निष्कर्ष देश का भविष्य केवल संसद, सरकार और योजनाओं से नहीं बनेगा। देश का भविष्य उस सामान्य नागरिक के जीवन से बनेगा जो सुबह उम्मीद लेकर घर से निकलता है और शाम को अपने परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य चाहता है। इसलिए विकास की दिशा में अगला कदम केवल नई सुविधाएं जोड़ना नहीं, बल्कि मौजूदा सुविधाओं को आम आदमी के लिए अधिक सुलभ, प्रभावी और संवेदनशील बनाना होना चाहिए। समाज की जरूरतें बढ़ रही हैं।

बोरीवली में आँगन वाडी मिलन कार्यक्रम विधायक संजय उपाध्याय के नेतृत्व में संपन्न

मुंबई (उत्तरशक्ति)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर मुंबई के बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय द्वारा अंगन का मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ विधायक संजय उपाध्याय ने संवाद साधा। आंगनवाडी सेविकाओं ने भी अपने नेता से अपनी आवश्यकता और कामकाज की पद्धति का ब्यौरा दिया। आंगन वाडी सेविकाओं के मुख पर आनंद और उत्साह का भाव देखने को मिला। आंगनवाडी सेविकाओं को शाल और भेंट वस्तु दी गई। इस अवसर पर उत्तर मुंबई भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष शीतल आम्ब्रे, भाजपा उत्तर मुंबई मीडिया प्रभारी नीला बेन सोनी, सभी नगरसेविका डॉ.शिल्पा संगोरे, जिज्ञ-ासा शाह, एड.सीमा शिंदे, श्वेता कोरगावकर, भाजपा बोरीवली अध्यक्ष सुरेखा ठोके, महिला मोर्चा की जयश्री पाटील, आदिवासी प्रकोष्ठ संयोजक पार्वती धोडी, उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ अध्यक्ष रागिनी सोनी, अलका खेरिया,मनीषा व्यास, रीना निकम एवं अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।

विधायक पराग शाह को जैन समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया

मुंबई (उत्तरशक्ति)। घाटकोपर पूर्व स्थित आराध्या भक्ति पार्क, हॉकी ग्राउंड में भारत जैन महामंडल की ओर से आयोजित सामूहिक क्षमापना, विश्व मैत्री दिवस एवं जैन समाज रत्न अलंकरण समारोह मंगलमय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। जनसंत श्रमण उपाध्याय 108 श्री विरंजनसागरजी म.सा., भ्रमण मुनि 108 श्री विसौम्यसागरजी म.सा., प.पू. मुनिराज श्री मुक्तिनिलय विजयजी म.सा., राष्ट्रसंत प.पू. गुरुदेव श्री नम्रमुनिजी म.सा. तथा आचार्य श्री महाश्रमणजी म.सा. की विदुषी शिष्या साध्वी श्री निर्वाणश्रीजी एवं साध्वी श्री डॉ. योगक्षेमप्रभाजी के पावन सान्निध्य में यह समारोह आयोजित किया गया। समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा की प्रमुख उपस्थिति रही। राज्यपाल के हाथों घाटकोपर पूर्व के विधायक पराग शाह को समाजसेवा, जनकल्याण एवं सामाजिक प्रतिबद्धता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जैन समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद विधायक पराग शाह ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरणादायी है। समाज के लिए किए गए सेवाभावी कार्यों की सराहना के रूप में मिला यह पुरस्कार उन्हें भविष्य में और अधिक उत्साह एवं निष्ठा के साथ समाजसेवा करने की प्रेरणा देगा। इस अवसर पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई की महापौर रितुताई तावडे, समाजसेवी शिवलाल पोखरणा सहित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारत जैन महामंडल की ओर से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी जैन समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया. क्षमाशीलता, मैत्री, सेवा और मानवता के मूल्यों को उजागर करने वाला यह समारोह समाजसेवा के लिए प्रेरणा देने वाला साबित हुआ।

एंटी-एक्सटॉर्शन स्क्वाड की दो बड़ी कार्रवाई, 90.32 लाख रुपये का प्रतिबंधित गुटखा और वाहन जब्त, पांच आरोपी गिरफ्तार

मीरा-भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा के एंटी-एक्सटॉर्शन स्क्वाड ने प्रतिबंधित गुटखे के खिलाफ दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए कुल 90 लाख 32 हजार 264 रुपये का माल जब्त किया है। पुलिस के अनुसार, कार्रवाई में बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ गुटखा तथा उसके परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों को जब्त किया गया है। पहले मामले में अब तक पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस ने दी है। आशा नगर में 44.67 लाख का माल जब्त पुलिस के मुताबिक, 3 सितंबर 2026 को मिली सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ एंटी-एक्सटॉर्शन स्क्वाड ने आशा नगर, कोल्ही चिंचोटी, तालुका वसई स्थित वाई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के परिसर में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 22 लाख 67 हजार 264 रुपये कीमत का प्रतिबंधित गुटखा बरामद किया गया। इसके अलावा करीब 20 लाख रुपये कीमत के तीन वाहनों को भी जब्त किया गया। इनमें टाटा ट्रक क्रमांक टल्ठ-15/ऋ-7419, टाटा इंट्रा टेम्पो क्रमांक टल्ठ-47/इफ-7842 तथा टाटा इंट्रा टेम्पो क्रमांक टल्ठ-48/ऊ-3988 शामिल हैं। इस कार्रवाई में कुल 44 लाख 67 हजार 264 रुपये का माल जब्त किया गया है। इस मामले में नायगांव पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 804/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की आगे की जांच अपराध शाखा के एंटी-एक्सटॉर्शन स्क्वाड द्वारा की जा रही है। पेल्हार में 45.65 लाख का माल पकड़ा दूसरी कार्रवाई 2 अक्टूबर 2026 को मिली सूचना के आधार पर पेल्हार, नालासोपारा पूर्व स्थित एप्पल इंडस्ट्रियल एस्टेट हब रोड पर की गई। कचरा कंपनी की दीवार के पास खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ बरामद किया। पुलिस के अनुसार, यहां से 31 लाख 65 हजार रुपये कीमत का गुटखा तथा करीब 14 लाख रुपये कीमत का आयशर ट्रक क्रमांक टल्ठ-04/खव-4706 और टाटा 407 टेम्पो क्रमांक टल्ठ-48/ऋ2213 जब्त किया गया। इस कार्रवाई में कुल 45 लाख 65 हजार रुपये का माल जब्त किया गया। इस मामले में पेल्हार पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 829/2026 दर्ज किया गया है।

स्कॉच अवार्ड मिलने के बाद भी मंत्री सरनाईक के योगदान का उल्लेख नहीं, प्रशासन पर उठे सवाल

मीरा-भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा-भायंदर नगर निगम की भारत की पहली सोलर कंट्रोल्ड विंड्रो कम्पोस्टिंग परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किए जाने के बाद अब इसके श्रेय को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह में नगर आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, उप महापौर ध्रुवकिशोर पाटिल और उप आयुक्त डॉ. सचिन बांगर ने पुरस्कार ग्रहण किया। हालांकि, पुरस्कार समारोह के दौरान परियोजना के लिए निधि उपलब्ध कराने और राजनीतिक स्तर पर सहयोग देने वाले परिवहन मंत्री तथा मीरा-भायंदर के जनप्रतिनिधि प्रताप सरनाईक के योगदान का उल्लेख नहीं किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। सरनाईक समर्थकों का आरोप है कि परियोजना को आगे बढ़ाने में उनकी दूरदृष्टि, राजनीतिक प्रयास और करीब 100 करोड़ रुपये की निधि महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के अवसर पर उनके योगदान का औपचारिक रूप से उल्लेख नहीं किया जाना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। 20 टन प्रतिदिन गीले कचरे के प्रसंस्करण की क्षमता नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र 146 के हाटकेश, मीरा रोड पूर्व और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर मैदान, भायंदर पूर्व में रउहउ परियोजना स्थापित की गई है। प्रत्येक परियोजना की क्षमता प्रतिदिन 20 टन गीले कचरे के प्रसंस्करण की बताई गई है। यह परियोजना सौर ऊर्जा आधारित तकनीक के माध्यम से गीले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करती है। इससे तैयार होने वाली जैविक खाद का उपयोग नगर निगम के उद्यानों, वृक्षारोपण अभियानों तथा स्थानीय किसानों के लिए किया जा सकता है। परियोजना IIT की पेटेंट तकनीक और SCWC प्रणाली पर आधारित होने का दावा किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एक परियोजना की स्वीकृत लागत 9,40,66,248 रुपये, जबकि दोनों परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत 18,81,32,496 रुपये बताई गई है। परियोजना के लिए ठेकेदार के रूप में मेसर्स लास ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उल्लेख किया गया है। SCWC परियोजना की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि मीरा-भायंदर को वर्ष 2025 में 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय

स्तर पर सम्मान मिला था। अब रउहउ परियोजना को मिला स्कॉच सिल्वर अवार्ड इस उपलब्धि को और मजबूती देने वाला माना जा रहा है।

पेंनकर पाड़ा परियोजना को लेकर भी सवाल: इसी बीच मीरा रोड के पेंनकर पाड़ा रिजर्वेशन क्रमांक 343 पर प्रतिदिन 20 टन गीले कचरे के प्रसंस्करण की क्षमता वाली सौर ऊर्जा आधारित यांत्रिक खाद परियोजना का काम शुरू होने की जानकारी सामने आई है। इसकी लागत करीब 9.44 करोड़ रुपये बताई गई है।

इसके अलावा 40 टन प्रतिदिन क्षमता वाली एक अन्य सौर ऊर्जा आधारित यांत्रिक खाद परियोजना की लागत करीब 21.75 करोड़ रुपये बताई गई है। आरोप है कि आधारभूत कार्य शुरू होने के बाद नगर निगम ने इस परियोजना का कार्यादेश रद्द कर दिया। इस मामले में परियोजना पर खर्च हुई राशि और कार्यादेश रद्द करने के कारणों को लेकर भी स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। सरनाईक समर्थकों का कहना है कि यदि पेंनकर पाड़ा की परियोजना पूरी होती, तो शहर के गीले कचरे के स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण को बड़ा बढ़ावा मिलता और कचरे के परिवहन व डंपिंग पर निर्भरता कम होती। 100 करोड़ रुपये की निधि का दावा

राजनीतिक पक्ष की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में विशेष प्रयासों के माध्यम से मीरा-भायंदर नगर निगम के अपशिष्ट एवं खाद प्रबंधन के लिए करीब 100 करोड़ रुपये की निधि स्वीकृत कराई गई थी।

समाज सेवक पंकज मिश्रा को लोगो ने दी जन्म दिन की बधाई

मीरा भायंदर (उत्तरशक्ति)। ठाणे समाज सेवक ,उद्योगपति एवं भाजपा नेता पंकज मिश्रा का जन्म दिन उनके शुभचिंतको ने उनके ठाणे स्थित कार्यालय में आकर मनाया। समाज सेवक पंकज मिश्रा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ रानीगंज से लेकर मुंबई तक समाज सेवा में सदैव तत्पर रहते है। साल में रानीगंज से लेकर मुंबई तक कई सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम कराने के बावजूद, दीन दुखियों की सहायता करना अपना दायित्व समझते है। जन्म दिन की बधाई देने वालो में मीरा रोड, ठाणे, मुंबई से लोगों का पूरा दिन तांता लगा रहा। बधाई देने वालो में मीरा भायंदर से शिवसेना नेता सुरेश दुबे, शिवसेना मीरा भायंदर उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार एवं भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा मीरा भायंदर जिला महामंत्री महेंद्र पाण्डेय, समाज सेवक रवि तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार अनिल शुक्ला, समाज सेवक प्रभाकर तिवारी के साथ साथ भारी संख्या में लोगों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दिए।

श्री दुर्गा मंदिर मान धाम में 11 से 20 अक्टूबर तक नवरात्रोत्सव व नवचंडी महायज्ञ का होगा भव्य आयोजन

पालघर(उत्तरशक्ति)। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर बोईसर पूर्व स्थित मान-महागांव लिंक रोड, नवापाड़ा, मान के मनोकामनापूर्ति श्री दुर्गा मंदिर मान धाम परिसर में जय अम्बे चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 11 से 20 अक्टूबर 2026 तक भव्य नवरात्रोत्सव एवं नवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जायेगा। पीठाधीश्वर संतश्री गुरुजी के सानिध्य में आयोजित इस धार्मिक महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती पाठ, भजन, आरती, कन्या पूजन, महाहवन एवं महाप्रसाद वितरण सहित विविध कार्यक्रम होंगे। आयोजकों के अनुसार 11 अक्टूबर को नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह 7 से 9 बजे तक पूजन एवं आरती होगी। इसके बाद

सुबह 11.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक कलश स्थापना, पूजन, महाआरती एवं प्रसाद वितरण किया जायेगा। दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक श्री दुर्गा सप्तशती पाठ तथा रात 8 से 9.30 बजे तक कलश पूजन, देवी पूजन, आरती एवं प्रसाद वितरण होगा। 12 से 19 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे तक कलश पूजन, देवी पूजन, भजन, आरती एवं प्रसाद वितरण, सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक श्री दुर्गा सप्तशती पाठ तथा रात 8 से 9.30 बजे तक कलश पूजन, आरती एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया जायेगा। वहीं 20 अक्टूबर को महानवमी एवं दशमी के अवसर पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सुबह 10 बजे से चलने वाले कार्यक्रम में सर्वप्रथम कलश पूजन, देवी पूजन, कन्या पूजन, महाआरती और सुबह 11.30 बजे महाहवन तथा दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक भजन एवं महाप्रसाद वितरण किया जायेगा। श्री दुर्गा मंदिर, मान धाम के पीठाधीश्वर संतश्री गुरुजी एवं समस्त सेवाधारियों की ओर से श्रद्धालुओं से परिवार एवं इष्ट-मित्रों के साथ मंदिर परिसर में पहुंचकर मां भगवती के चरणों में श्रद्धा-सुमन अर्पित करने तथा नवरात्रोत्सव एवं नवचंडी महायज्ञ के धार्मिक आयोजन का लाभ लेने का आहवान किया है। कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष क्र. 9284807557 पर संपर्क कर सकते हैं।

समाजसेवक साहिल जाधव ने स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर के साथ मनाया जन्मदिन

पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। समाजसेवा को प्राथमिकता देते हुए समाजसेवक साहिल सुरेश जाधव ने अपना जन्मदिन सामाजिक सरोकार से जोड़कर मनाया। उनके जन्मदिन के अवसर पर संजीवन मैत्रेय फाउंडेशन की ओर से बोईसर के भीमनगर बुद्ध विहार परिसर में निःशुल्क मेडिकल कैंप एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। मेडिकल कैंप में नागरिकों की जनरल हेल्थ चेकअप, सीबीसी टेस्ट, डायबिटीज जांच एवं नेत्र जांच की गई। वहीं रक्तदान शिविर के माध्यम से करीब 35 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इस दौरान रक्तदाताओं ने

उत्साहपूर्वक रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए समाज को प्रेरणादायी संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान केक काटकर साहिल सुरेश जाधव का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन जैसे व्यक्तिगत अवसर को समाजसेवा से जोड़ते हुए आयोजित इस पहल के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ ही रक्तदान के महत्व का संदेश दिया गया। रक्त संग्रह के लिए महाराष्ट्र ब्लड बैंक, पालघर की टीम ने सहयोग प्रदान किया। इस कार्य में वैशाली चव्हाण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं मेडिकल कैंप में डॉ. राजेंद्र चव्हाण एवं उनकी मेडिकल टीम ने नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं।इस अवसर पर समाजसेवक ब्रह्मदेव चौबे, मुकेश पाटील, प्रशांत संखे, श्रवण मिश्रा, विकास शुक्ला, अजय शेरे, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश करोतीया, प्रमोद गजभिये, उमाकांत भारती सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।कार्यक्रम के आयोजन में एड. सुरेश जाधव, मुख्तार खान, नासिर खिलजी, दक्ष मर्दे एवं प्रिन्स सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

बचत समूहों को बाजार से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें महिलाएं

सेवा संकल्प अभियान के तहत डहाणू में राणी दुर्गावती महिला सशक्तीकरण मेला आयोजित

पालघर(उत्तरशक्ति)। महिलाओं को केवल बचत समूहों तक सीमित न रखते हुए उन्हें उत्पादन, बाजार और आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ने के उद्देश्य से सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत डहाणू में राणी दुर्गावती महिला सशक्तीकरण मेले का आयोजन किया गया। डहाणू एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना की ओर से के. एल. पोंडा हाईस्कूल, पारनाका, डहाणू में आयोजित इस मेले में डहाणू एवं तलासरी क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं, महिला बचत समूहों की प्रतिनिधियों तथा विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मेले में महिला सशक्तीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार तथा बचत समूहों के माध्यम से उपलब्ध विभिन्न अवसरों की जानकारी दी गई। महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने पैरों पर खड़े होने तथा बचत समूहों को व्यवसाय का मजबूत माध्यम बनाने का संदेश दिया गया। मेले का प्रमुख आकर्षण महिला बचत समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री रहा। इसमें चिकू से बने विभिन्न उत्पादों, घरेलू स्नैक्स सहित अनेक वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए। स्थानीय संसाधनों और महिलाओं के

कौशल से तैयार उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण रही। इस दौरान बताया गया कि महिलाओं के कौशल को व्यवसाय से जोड़ने पर परिवार की आय में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों की महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बन सकती हैं। इसके लिए बचत समूहों के उत्पादों को उचित बाजार उपलब्ध कराने तथा उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ना आवश्यक है। मेले में शामिल महिलाओं की स्वास्थ्य जांच भी की गई। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। इसके अलावा विभिन्न महिला सशक्तीकरण योजनाओं, स्वरोजगार के अवसरों, बचत समूहों के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया की जानकारी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने दी। डहाणू एवं तलासरी क्षेत्र के महिला बचत समूहों ने मेले में उत्साहपूर्वक सहभागिता दर्ज कराई। उत्पादों की प्रदर्शनी, बिक्री, मार्गदर्शन और स्वास्थ्य जांच के माध्यम से महिलाओं को एक ही मंच पर आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हुई। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित इस मेले ने आदिवासी महिलाओं को सशक्तीकरण, स्वावलंबन, उद्यमिता, स्वास्थ्य जागरूकता और सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रभावी मंच उपलब्ध कराया। कार्यक्रम में एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना के अधिकारी एवं कर्मचारी, विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी, महिला बचत समूहों की प्रतिनिधियां तथा क्षेत्र के नागरिक उपस्थित रहे।

अलहम्द हाई स्कूल में आवेदन पत्र लेखन प्रतियोगिता में 75 विद्यार्थियों ने लिया भाग

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। विद्यार्थियों में लेखन कौशल और भाषाई दक्षता विकसित करने के उद्देश्य से अलहम्द इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आवेदन पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। अंग्रेजी, मराठी, उर्दू और हिंदी चार भाषाओं में हुई इस प्रतियोगिता में 75 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंग्रेजी भाषा में शेख फराह शहजाद ने प्रथम, शेख रोमा एजाज ने द्वितीय तथा सिद्दीकी नवेद शकील ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मराठी में खान फरहान अमजद अली प्रथम, मंतशा परवेज मोमिन द्वितीय तथा शाह शफक शकील तृतीय रहे। उर्दू में खान बुशरा आबिद प्रथम, शाह

शफक द्वितीय तथा शेख हफ्सा तौकीर आलम तृतीय रहीं। हिंदी में अंसारी यासमीन प्रथम, शेख रोमा एजाज द्वितीय तथा शेख हफ्सा तौकीर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

विजेता विद्यार्थियों को 7 अक्टूबर को स्कूल के चेयरमैन अब्दुल अजीज अंसारी एवं एडमिनिस्ट्रेटर निहाल अहमद के हाथों पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रभारी रुकैया पटेल, प्रतियोगिता संयोजक अबुल कलाम, खान लुबना सहित शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। विद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रभावी लेखन एवं अभिव्यक्ति क्षमता विकसित करना तथा व्यावहारिक जीवन में आवेदन पत्र लेखन के महत्व से परिचित कराना है।

भिवंडी मनपा के विरोध में मूलभूत सुविधाओं को लेकर सीपीआई का आंदोलन

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। भिवंडी शहर की झोपड़पट्टियों और विभिन्न रहवासी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ठाणे जिला कौन्सिल की ओर से मंगलवार को भिवंडी मनपा मुख्यालय पर आंदोलन किया गया। कॉ. विजय कांबले के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में मनपा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नागरिक समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की गई। सीपीआई की ओर से मनपा आयुक्त को पहले दिए गए निवेदन में आरोप लगाया गया था कि शहर के मजदूर और झोपड़पट्टी क्षेत्रों में पेयजल, गटर सफाई, सड़क तथा पथदीप जैसी मूलभूत सुविधाओं की गंभीर समस्या बनी हुई है। शांतिनगर क्षेत्र की गटरों की कई वर्षों से सफाई नहीं होने का आरोप भी लगाया गया। सीपीआई के अनुसार गोविंदनगर, रहमतपुर, जब्बार कंपाउंड, बांदेल नगर, फातिमा नगर, 60 फीट रोड, गायत्रीनगर, नागांव, गणेशनगर और कामतघर सहित कई क्षेत्रों में पानी की समस्या गंभीर है। कुछ इलाकों में 8 से 20 दिनों तक पानी नहीं मिलने का दावा करते हुए नई बस्ती में भी नियमित जलापूर्ति शुरू करने की मांग की गई। इसके अलावा सड़कों पर लगाए गए कई रोडलाइट बंद होने से नागरिकों को रात में अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलकों ने गटरों की नियमित सफाई, सुचारु जलापूर्ति, सड़कों की मरम्मत तथा बंद रोडलाइटों को तत्काल शुरू करने की मांग की।

आईसीआईसीआई बैंक ने खरीदारी, यात्रा और लाइफस्टाइल ब्रांड्स पर आकर्षक ऑफर के साथ फेस्टिव बोनांजा की फिर की शुरूआत

मुंबई/पटना। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने वार्षिक फेस्टिव बोनांजा ऑफर की फिर शुरूआत की है। इसके तहत ऑनलाइन खरीदारी, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, यात्रा, फर्नीचर और होम डेकोर, फैशन, क्विक कॉमर्स सहित कई क्षेत्रों के प्रमुख ब्रांड्स पर आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं। ग्राहक आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कार्डलेस ईएमआई और नो-कॉस्ट ईएमआई विकल्पों के जरिए विशेष ऑफर, छूट और कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं।

बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 8 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। इस दौरान ग्राहक विभिन्न उत्पादों की खरीदारी पर 10% की छूट का लाभ उठा सकेंगे।

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय :
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामीः शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

मेरठ में युवक की संदिग्ध मौत हत्या के मुकदमे में बदली, पत्नी व कथित प्रेमी पर केस

मेरठ (उत्तरशक्ति)। लोहियानगर थाना क्षेत्र के फतेहउल्लापुर निवासी 30 वर्षीय राजमिस्त्री तालिब की 28 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब हत्या के मुकदमे में बदल गया है। मृतक के चचेरे भाई अकरम की तहरीर पर पुलिस ने तालिब की पत्नी इल्मा और अमन नामक ब्यूटी स्टूडियो संचालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।

बताया गया कि तालिब की मौत के बाद उसकी पत्नी ने परिजनों को इसे स्वाभाविक मौत बताया था। इसके बाद शव को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में दफना दिया गया। बाद में परिजनों ने अंतिम संस्कार से पहले खींची गई तस्वीरों को देखा तो तालिब के गले पर संदिग्ध निशान दिखाई देने का दावा किया। इसके बाद उन्होंने हत्या की आशंका जताई।

परिजनों के अनुसार तालिब का मोबाइल भी गायब था, जो 2 अक्टूबर को कपड़ों के बीच मिला। मोबाइल में मिली बातचीत, कॉल डिटेल और वॉयस रिकॉर्डिंग के आधार पर परिजनों ने उसकी पत्नी इल्मा और अमन के बीच कथित संबंध होने का आरोप लगाया। दोनों पर मिलकर तालिब की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। परिवार की ओर से पुलिस को एक कथित वीडियो भी दिए जाने की बात सामने आई है, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

कब्र से निकलेगा शव, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज: पुलिस अब मुजफ्फरनगर में दफन तालिब के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में है। इसके लिए संबंधित प्रशासन से अनुमति की प्रक्रिया शुरू की गई है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा दें: कुलपति

विज्ञान संकाय की प्रगति को लेकर दिए दिशा-निर्देश

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। संकाय भवन में संचालित विज्ञान संकाय में शैक्षणिक, शोध एवं औद्योगिक विकास को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह ने विज्ञान संकाय के विभिन्न विभागों की प्रगति एवं भविष्य की कार्ययोजना की समीक्षा की।

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने कुलपति का स्वागत किया तथा विज्ञान संकाय एवं विभिन्न विभागों की प्रगति आख्या प्रस्तुत की। उन्होंने विभागों में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, शोध कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह ने विभिन्न विभागों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों को शिक्षण एवं शोध के साथ-साथ उद्योगों से समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों को रोजगारपरक एवं व्यावहारिक शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

कुलपति ने बोर्ड ऑफ स्टडीज में उद्योग जगत के विशेषज्ञों को शामिल करने तथा औद्योगिक संस्थानों के साथ एमओयू करने पर जोर दिया।

उन्होंने प्रत्येक विभाग को आगामी 10 वर्षों में विभाग की उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही वर्ष 2047 तक पूरे विश्वविद्यालय की प्रगति एवं विकास के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करने की बात कही।

कुलपति ने विज्ञान संकाय के विभागों को शोध कार्यों को बढ़ावा देने, अधिक से अधिक शोध परियोजनाएं एवं पेटेंट विकसित करने तथा विद्यार्थियों को नई तकनीकों एवं औद्योगिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए औद्योगिक भ्रमण आयोजित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विज्ञान संकाय को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए शिक्षण, शोध, नवाचार, उद्योग-अकादमिक सहयोग और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। प्रत्येक विभाग अपनी उपलब्धियों के साथ-साथ भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ठोस एवं परिणामपरक कार्ययोजना तैयार करे।

बैठक में प्रो. रामनारायण, प्रोफेसर राजेश शर्मा, डॉ. मनीष गुप्ता, प्रोफेसर प्रमोद यादव, प्रोफेसर गिरधर मिश्र, डॉ. विवेक पाण्डेय, डॉ. ऋषि श्रीवास्तव, डॉ. राधिका, डॉ. अमित गुप्त, डॉ. विपिन कुमार एवं डॉ. एस.पी. तिवारी सहित विज्ञान संकाय के शिक्षक उपस्थित रहे।

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दक्षता विकसित करें विद्यार्थी: प्रो.राकेश कुमार सिंह

◆ सुरक्षित एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बारीकियां पर हुई चर्चा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 'सिक्योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट' विषय पर आयोजित छह दिवसीय कार्यशाला के द्वितीय दिवस में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कार्यशाला में मुख्य विषय विशेषज्ञ के रूप में देश के प्रख्यात साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ. अनूप गिरधर ने विद्यार्थियों को सुरक्षित एप्लीकेशन डेवलपमेंट के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी।

कार्यक्रम में कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में साइबर सुरक्षा और सिक्योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के क्षेत्र में भविष्य की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की रुचि और सहभागिता इसी प्रकार बनी रही तो विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में और भी अधिक प्रायोगिक एवं इंडस्ट्री ओरिएंटेड कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा के साथ व्यावहारिक तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो सके।

तकनीकी सत्र में विषय विशेषज्ञ डॉ. अनूप गिरधर ने विद्यार्थियों को प्रोग्रामिंग की मूलभूत अवधारणाओं से लेकर सिक्योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के तकनीकी पक्ष को सरल एवं व्यावहारिक तरीके से समझाया। उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि सुरक्षित और मजबूत एप्लीकेशन के निर्माण में किन सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना आवश्यक है।

सत्र की प्रमुख कड़ी हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग रही। डॉ. गिरधर ने विद्यार्थियों को लाइव प्रोग्रामिंग के माध्यम से वर्चुअल मशीन सेटअप करने तथा कोड में आवश्यक सुरक्षा मानकों को लागू करने का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने स्वयं तकनीकी गतिविधियों में भाग लेते हुए सुरक्षित एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बारीकियों को समझा।

कार्यशाला में 90 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का आयोजन इंजीनियरिंग संकाय के संकायाध्यक्ष प्रो. सौरभ पाल के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रो. अशोक श्रीवास्तव, प्रो. गिरिधर मिश्र, प्रो. राजकुमार, , डॉ. दिव्येंदु मिश्र, प्रियंका जायसवाल सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

ऑपरेशन मुस्कान के तहत शाहगंज पुलिस ने अपहृता को सकुशल बरामद किया

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देश पर अपहृत/अपहृता की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत शाहगंज पुलिस ने एक अपहृता को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार, थाना शाहगंज में 2 अक्टूबर 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 339/2026 के तहत धारा 137(2), 87 बीएनएस में मामला दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस टीम लगातार अपहृता की बरामदगी के लिए प्रयासरत थी। इसी क्रम में मंगलवार 6 अक्टूबर को पुलिस ने अपहृता को सकुशल बरामद कर लिया।

पुलिस ने बताया कि अपहृता के स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है तथा नियमानुसार बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उसकी गरिमा, गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक अजय कुमार सिंह, कांस्टेबल सिजाउद्दीन शेख तथा महिला कांस्टेबल रीता चौहान शामिल रहीं।

मुख्यमंत्री से कुलपति प्रो.राकेश कुमार सिंह ने की शिष्टाचार भेंट

विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों एवं भावी योजनाओं से मुख्यमंत्री को कराया अवगत

लखनऊ/जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की।

इस दौरान कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न शैक्षणिक एवं विकासात्मक विषयों की जानकारी दी। उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, उपलब्धियों तथा भविष्य की योजनाओं से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय की प्रगति तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे गुणवत्तापूर्ण कार्यों के लिए कुलपति को शुभकामनाएं दीं।

दूध से पनीर तक संरक्षण की वैज्ञानिक तकनीक जरूरी: प्रो.सुधीर सिंह

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के संरक्षण पर विशेष व्याख्यान आयोजित

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में संचालित फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर 'दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के संरक्षण' विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी के पूर्व वैज्ञानिक प्रो. सुधीर सिंह ने विद्यार्थियों को दुग्ध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादों के संरक्षण की वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानव द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का बड़ी मात्रा में सेवन किया जाता है। ऐसे में इनकी गुणवत्ता, पोषणात्मक मूल्य और खाद्य सुरक्षा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। दूध, पनीर के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है।

प्रो. सुधीर सिंह ने कहा कि दुग्ध अत्यधिक शीघ्र खराब होने वाला खाद्य पदार्थ है। इसकी गुणवत्ता, पोषणात्मक मूल्य एवं सुरक्षित शेल्फ लाइफ बनाए रखने के लिए उचित प्रसंस्करण, ताप उपचार, शीत भंडारण, स्वच्छता और प्रभावी पैकेजिंग अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।उन्होंने विशेष रूप से दूध, पनीर और बटर के संरक्षण की तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की। पनीर के संदर्भ में उन्होंने इसके निर्माण, नमी नियंत्रण, स्वच्छता, पैकेजिंग, शीत भंडारण तथा गुणवत्ता बनाए रखने के उपायों की जानकारी दी। वहीं बटर के संरक्षण में तापमान नियंत्रण, उचित पैकेजिंग, ऑक्सीकरण से सुरक्षा तथा भंडारण की उपयुक्त परिस्थितियों के महत्व को समझाया।उन्होंने विद्यार्थियों को बटर, क्रीम, मिल्क पाउडर सहित अन्य दुग्ध उत्पादों के संरक्षण एवं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली आधुनिक तकनीकों से भी अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक संरक्षण तकनीकों का उपयोग न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि दुग्ध उत्पादों के मूल्यवर्धन और उनके व्यावसायिक उपयोग की संभावनाओं को भी बढ़ाता है।

व्याख्यान के दौरान विद्यार्थियों ने दूध, पनीर, बटर एवं अन्य दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका प्रो. सुधीर सिंह ने विस्तारपूर्वक समाधान किया।कार्यक्रम के अंत में संकायाध्यक्ष प्रो. प्रदीप कुमार ने प्रो. सुधीर सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया।

दीपावली को लेकर शंकर झनकार नाट्यकला परिषद की बैठक

पुरानी कमेटी भंग, सर्वसम्मति से अरविंद जायसवाल बने अध्यक्ष

महुली, सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। दीपावली पर्व के आयोजन को लेकर शंकर झनकार नाट्यकला परिषद (पूर्व), महुली की आवश्यक बैठक रविवार को सुदेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के ग्रामीणों और परिषद से जुड़े सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैठक में आगामी दीपावली कार्यक्रमों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों एवं परिषद के सदस्यों की सर्वसम्मति से पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया गया। नई कमेटी में अरविंद जायसवाल को अध्यक्ष चुना गया। वहीं संजीव जौहरी को मुख्य संरक्षक, शेकरार अहमद को उपाध्यक्ष, प्रदीप जायसवाल को प्रबंधक, दीपक कुमार कनौजिया एडवोकेट को उपप्रबंधक, भगवान दास को कोषाध्यक्ष तथा दिलीप जायसवाल को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई।

अध्यक्ष चुने जाने के बाद अरविंद जायसवाल ने सभी ग्रामीणों एवं परिषद के सदस्यों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और आपसी एकजुटता से दीपावली के कार्यक्रमों को बेहतर एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाएगा।

नई कमेटी के पदाधिकारियों एवं उपस्थित ग्रामीणों ने परिषद के आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने, आपसी सहयोग बनाए रखने तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में दीपावली पर्व मनाने का संकल्प लिया। नई कमेटी के गठन और अरविंद जायसवाल के अध्यक्ष चुने जाने से परिषद से जुड़े सदस्यों एवं ग्रामीणों में उत्साह का माहौल रहा।

मामूली विवाद में कलयुगी बेटे ने पिता पर नुकीली चीज से किया हमला

गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार मोहल्ले से एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ घरेलू बात को लेकर हुए विवाद में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता पर नुकीली वस्तु से हमला कर दिया। इस हमले में पिता गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार, पुरानी बाजार निवासी घूरेलाल गुप्ता 60वर्ष का अपने बेटे सुभाष से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि बडा बेटा सुभाष ने आपा खो दिया और घर में रखी एक नुकीली चीज उठाकर अपने पिता घूरेलाल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में घूरेलाल के शरीर से भारी मात्रा में खून बहने लगा और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे तथा घायल घूरेलाल को आनन-फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर आरोपी बेटे सुभाष के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना से पूरे मोहल्ले में सनसनी और दहशत का माहौल है।

पेड़ से नाबालिग को बांधकर पीटने के तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

गौराबादशाहपुर,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गौराबादशाहपुर थाना पुलिस ने मंगलवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लाइनबाजार थाना क्षेत्र के चकराजेपुर पचोखर निवासी नाजमा पत्नी शमशेर ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनका बेटा रोहित अपने दोस्तों छोटू और गोदीवाले के साथ मोपेड से गौराबादशाहपुर जा रहा था। इसी दौरान विपक्षियों ने उन्हें रोककर पेड़ से बांध दिया और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी थी। मामले की विवेचना कर रहे उपनिरीक्षक अवधेश कुमार पुलिस टीम के साथ केशवपुर गांव में आरोपियों से पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी आपस में कहासुनी करने लगे और उत्तेजित होकर अनाप-शनाप बोलने लगे। शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान केशवपुर निवासी अबुल कश्यप, पवन मौर्य और दिलीप मौर्य के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों का चालान कर न्यायालय भेज दिया गया है।

आंधी-पानी ने धान की फसल पर ढाया कहर, खेतों में बिछी तैयार फसल

नदौली समेत कई गांवों में भारी नुकसान, किसानों ने सर्वे कर मुआवजा दिलाने की उठाई मांग

केराकत,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। बीती रात तेज आंधी और बारिश ने क्षेत्र के किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तेज हवा के साथ हुई बारिश से धान की तैयार फसल खेतों में गिरकर बिछ गई। अचानक बदले मौसम से किसानों की चिंता बढ़ गई है। नदौली, डेढ़ुवाने, अकबरपुर, मुर्की, डेहरी और सूरतपुर समेत आसपास के कई गांवों में धान की फसल को भारी नुकसान होने की बात सामने आई है।

किसानों के अनुसार अधिकांश खेतों में धान की फसल पककर तैयार होने के करीब थी। इसी दौरान तेज आंधी आने से फसल जमीन पर गिर गई। खेतों में फसल के गिर जाने से अब कटाई में भी परेशानी होगी। वहीं बारिश जारी रहने पर गिरी हुई फसल के सड़ने और धान के दाने खराब होने की आशंका भी बढ़ गई है। इससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है।

किसानों ने बताया कि धान की खेती में बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी समेत काफी खर्च हो चुका है। फसल तैयार होने के समय मौसम की मार ने उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। कई खेतों में धान की बालियां जमीन से सट गई हैं, जिससे फसल को संभालना मुश्किल हो गया है। किसान दीपनारायण सिंह समेत अन्य किसानों ने प्रशासन से प्रभावित गांवों में तत्काल राजस्व विभाग की टीम भेजकर खेतों का निरीक्षण कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि गांव-गांव पहुंचकर फसल क्षति का सर्वे कराया जाए और नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जाए। इसके आधार पर प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाए, ताकि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की कुछ भरपाई हो सके।

दीपनारायण सिंह ने कहा कि धान की फसल तैयार होने के समय आंधी और बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कई खेतों में फसल पूरी तरह जमीन पर गिर गई है। इससे पैदावार प्रभावित होने के साथ कटाई में भी परेशानी होगी। प्रशासन को तत्काल प्रभावित गांवों का सर्वे कराकर किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिलाना चाहिए।

वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प बाइक यात्रा का जौनपुर में भव्य स्वागत

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि वडनगर, गुजरात से कर्मभूमि वाराणसी तक निकली 'सेवा संकल्प बाइक यात्रा' का जौनपुर में विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के माध्यम से सेवा, समर्पण, राष्ट्र निर्माण और जनभागीदारी का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा के पहुंचने पर विधायक रमेश चन्द्र मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सिंगरामऊ, भगवान श्री परशुराम प्रवेश द्वार और करमपुर में यात्रा का स्वागत किया।

जौनपुर में आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चन्द्र यादव, विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह 'प्रिंसु', महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी शंकर गिरी तथा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने यात्रा में शामिल युवाओं का स्वागत किया और उन्हें संबोधित किया।

राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने कहा कि यह यात्रा सेवा, समर्पण और जनकल्याण की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के साथ राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और मजबूत करने का संदेश दे रही है। उन्होंने युवाओं से सामाजिक सरोकारों और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

विधायक रमेश चन्द्र मिश्रा ने कहा कि जन्मभूमि वडनगर से कर्मभूमि वाराणसी तक की यह यात्रा भारत को एक सूत्र में जोड़ने के संकल्प का प्रतीक है। यात्रा के दौरान सेवा गतिविधियों, जनसंपर्क और सामाजिक भागीदारी के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है।

यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान, दर्शन-पूजन, वृक्षारोपण और गो-पूजन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की सेवा, समर्पण एवं राष्ट्र निर्माण के संकल्प को जनसामान्य तक पहुंचाने का माध्यम बताया गया।

यात्रा धनियामऊ होते हुए मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के हौज पहुंची। यहां मछलीशहर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. अजय सिंह के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और यात्रियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, युवा एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

महुली में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर बैठक

दशहरा के बाद होगा छठ पूजा सेवा समिति का चुनाव

महुली, सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। आगामी छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर सोमवार को महुली फील्ड ग्राउंड में पूर्व छठ पूजा सेवा समिति के तत्वावधान में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी उर्फ बबलू चौधरी ने की। इसमें छठ पूजा के सफल आयोजन एवं समिति के आगामी चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में उपस्थित ग्रामीणों की आपसी सहमति से निर्णय लिया गया कि दशहरा पर्व के बाद छठ पूजा सेवा समिति का चुनाव कराया जाएगा। साथ ही छठ पूजा के दौरान होने वाले कार्यक्रमों को व्यवस्थित एवं सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में विंढमगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, मंडल महामंत्री पंकज गोस्वामी, लेखपाल मनोज कुमार कनौजिया, पंकज कनौजिया, मनोज भारती, पितरम सिंह गोंड, समाजसेवी उदय शर्मा, नंदू गुप्ता, देवेंद्र यादव, मुलायम यादव, उपेंद्र श्रीवास्तव, विकास कुमार कनौजिया, अंशु कुमार, आकाश कुमार, आलोक कनौजिया, सूरज कुमार, शिवम कनौजिया, नितेश कुमार छोटनी सहित अन्य ग्रामीण एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

इस दौरान सभी गांवों के सम्मानित नागरिकों एवं ग्रामीणों से आगामी बैठक में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने सुझाव देने की अपील की गई। लोगों से आपसी सहयोग, एकजुटता और सामूहिक सहभागिता के साथ छठ महापर्व के आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया गया।

ग्रामीणों ने कहा कि छठ महापर्व के कार्यक्रम को बेहतर एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी लोग मिलकर सहयोग करेंगे। बैठक के बाद ग्रामीणों में छठ पूजा को लेकर उत्साह का माहौल रहा।

राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे पीयू के प्रतिभागी

लखनऊ में आयोजित होगी राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2026 को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में 'मेरे सपनों का भारत' विषय पर विश्वविद्यालय स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय परिसर के छात्र अभिनव कीर्ति पांडेय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय, केराकत (जौनपुर) की छात्रा राधा गिरी ने द्वितीय स्थान और डॉ. राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय, मुड़ीतागंज (जौनपुर) के छात्र मनीष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागी 7 अक्टूबर 2026 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के केंद्रीय पुस्तकालय स्थित सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में डॉ. शशिकांत यादव एवं डॉ.उदयभान यादव भी उपस्थित रहेंगे।

कुलपति ने छात्रों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित किया । इस अवसर पर प्रो प्रमोद कुमार यादव, प्रो. अजय प्रताप सिंह, कुलसचिव, वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय ने भी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित किया।

शिव कामगार सेना में राजेश गावकर और नितिन कदम की नियुक्ति

पालघर। शिवसेना कामगार संगठन में संगठनात्मक जिम्मेदारियों का विस्तार करते हुए राजेश गावकर को पालघर जिला उपाध्यक्ष तथा नितिन कदम को जिला सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। दोनों पदाधिकारियों को पालघर जिला प्रमुख नीलेश तेंदुलकर ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और संगठन के प्रति जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला सचिव अतुल पाटिल, शिव कामगार सेना के जिला अध्यक्ष शैलेश जाधव तथा जिला उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश मिश्रा ह्यपिंटूह्न सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कामगारों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठाने और संगठन को मजबूत करने की बात कही।

भदोही के कालीनों पर दुनिया की मुहर, खरीदारों ने खोली कारोबार की नई राह

-सुरेश गांधी

भदोही। कालीन सिर्फ धागों, रंगों और गांठों से नहीं बनता। उसके पीछे पीढ़ियों का हुनर, महीनों की मेहनत और बदलते बाजार को समझने वाली नजर होती है। भदोही में चल रहा गोल्डन जुबली 50वां इंडिया कार्पेट एक्सपो इसी बदलती कहानी का साक्षी बन रहा है। तीसरे दिन तक दुनिया के अलग-अलग देशों से आए 212 से अधिक विदेशी खरीदारों और 231 बाइंग रिप्रेजेंटेटिव्स ने भारतीय कालीनों के नए संग्रहों को परखा। किसी ने डिजाइन में भविष्य की झलक देखी तो किसी ने रंगों में अपने बाजार की पसंद तलाश की।

स्टॉलों पर चलती बातचीत और कारोबारी पूछताछ ने यह संकेत दिया कि भदोही के करघों की आवाज अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रही। अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न देशों से आए खरीदारों की दिलचस्पी ने एक्सपो

में कारोबार की उम्मीदों को नई रोशनी दी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप तैयार किए गए नए डिजाइन, आकार, रंग, गुणवत्ता और समकालीन पैटर्न खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं। परंपरा के साथ आधुनिकता का यह मेल भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग के लिए नई पहचान गढ़ता दिखाई दे रहा है।

कालीन से आगे बढ़कर बाजार की तैयारी

इस बार एक्सपो की खासियत सिर्फ कालीनों की चमक नहीं, बल्कि उद्योग के भीतर हो रहा बदलाव भी है। डिजाइन अब केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग बाजारों की पसंद और जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार हो रहे हैं। टिकाऊ उत्पाद, नए पैटर्न, समकालीन रंग संयोजन और गुणवत्ता पर जोर इस बदलाव के प्रमुख संकेत हैं। इसी बदलती जरूरत को संस्थागत ताकत देने के लिए कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (CEPC)और Walmart Vriddhi के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ज्ञान-साझाकरण सत्र में Walmart Vriddhi के एसोसिएट डायरेक्टर आदित्य वर्मा ने उद्यमियों और एमएसएमई के लिए उपलब्ध अवसरों और कार्यक्रमों की जानकारी दी। समझौते का उद्देश्य क्षमता निर्माण, कारोबार के विकास, ज्ञानवर्धन और बाजार तक पहुंच के अवसर बढ़ाना है। यानी भदोही के करघे अब केवल कालीन नहीं बुन रहे, बल्कि वैश्विक बाजार के लिए अपने कारोबार की नई भाषा भी सीख रहे हैं। गोल्डन जुबली का एक भावुक पड़ाव उन लोगों का सम्मान रहा, जिन्होंने वर्षों तक CEPC और भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग को मजबूत करने में भूमिका निभाई। पूर्व अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और प्रशासन समिति के पूर्व सदस्यों को सम्मानित किया गया। सम्मानित सदस्यों ने अपने अनुभव साझा करते हुए इंडिया कार्पेट एक्सपो के सफर को याद किया। यह सम्मान दरअसल उस पीढ़ी को सलाम था, जिसने इस मंच की नींव मजबूत की और आज जिसकी बदौलत दुनिया के खरीदार भदोही तक पहुंच रहे हैं।

2020 के बाद से भारत में डेटा सेंटर क्षमता चार गुना से भी अधिक बढ़ी

मुंबई। क्लाउड अपनाने में तेजी, 5G सेवाओं के प्रसार, डेटा लोकलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की बढ़ती मांग के बल पर भारत का डेटा सेंटर उद्योग तीव्र विस्तार के दौर से गुजर रहा है। देश में डेटा सेंटर की परिचालन क्षमता (ऑपरेशनल कैपेसिटी) 2020 में लगभग 375 मेगावाट से बढ़कर 2025 में 1,575 मेगावाट से अधिक हो गई है। अनुमानों के अनुसार, 2030 तक यह क्षमता 4.5 से 9 गीगावाट तक पहुँच सकती है। इस क्षेत्र ने 2019 से 2025 के बीच अनुमानित 95 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी निवेश आकर्षित किया है।

पॉलिसी कंसेंसस सेंटर (पीसीसी) द्वारा जारी एक नए चर्चा पत्र, जिसका शीर्षक ह्यलिविंग नेक्स्ट टू द क्लाउडः एन एविडेंस-बेस्ड अप्रोच टू डेटा सेंटर्स इन रेसिडेंशियल इंडिया है, में अध्ययन किया गया है कि डेटा सेंटर सुविधाओं के आसपास रहने वाले रिहायशी समुदायों के साथ इस विस्तार का सही प्रबंधन कैसे किया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य प्रश्न अब यह नहीं है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को शहरी क्षेत्रों से बाहर रखा जाए या नहीं, बल्कि यह है कि डेटा सेंटर और रिहायशी इलाके आपस में बेहतर सह-अस्तित्व कैसे बनाए रख सकते हैं। पॉलिसी कंसेंसस सेंटर (पीसीसी) द्वारा महाराष्ट्र (ठाणे, ऐरोली, नवी मुंबई) और तमिलनाडु (चेन्नई) में डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए सरकारी परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर उपलब्ध पर्यावरण क्लीयरेंस फाइलों की समीक्षा में कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं। बिजली और ऊर्जा दक्षता की बात करें तो भारत में डेटा सेंटरों की बिजली मांग 2024 में 1.4 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 9 गीगावाट पहुँचने का अनुमान है।

नाट्यगृह के उद्घाटन पर प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप

विधायक स्नेहा दुबे-पंडित ने मेयर के बयान पर जताई आपत्ति

वसई। वसई-विरार शहर के बोलिंज स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अचोले स्थित नाट्यगृह के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर विवाद सामने आया है। वसई विधायक स्नेहा दुबे-पंडित ने महानगरपालिका के मेयर पर सरकारी प्रोटोकॉल और प्रशासनिक नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। विधायक ने मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए कथित बयान, ह्नसरकारी फैसला (जीआर) कानून नहीं होताह्न, पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के फ्ि‍ीर ड्ड ि४ल्ली२२ तथा संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत जारी सरकारी आदेशों का प्रशासनिक महत्व है और सार्वजनिक धन से निर्मित इमारतों के उद्घाटन में निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। स्नेहा दुबे-पंडित ने 11 जुलाई 2019 के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सरकारी निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नयी मुंबई महानगरपालिका में केवल मेयर को उद्घाटन का अधिकार देने वाले प्रस्ताव को सरकार ने रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि इससे महानगरपालिका के कार्यक्रमों में प्रशासनिक प्रक्रिया और आधिकारिक शिष्टाचार के महत्व का पता चलता है। विधायक ने महानगरपालिका आयुक्त की प्रशासनिक भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि निमंत्रण पत्र तैयार करने, नामों का क्रम तय करने और मंच पर बैठने की व्यवस्था जैसे विषयों में निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। उन्होंने कहा कि केवल निमंत्रण भेज देना ही शिष्टाचार का पालन नहीं माना जा सकता।

उन्होंने सार्वजनिक इमारत के उद्घाटन से पहले फायर एनओसी, स्ट्रक्चरल ऑडिट और ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (इवद) जैसी आवश्यक मंजूरियों का मुद्दा भी उठाया। साथ ही सवाल किया कि यदि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह शुरू होने में अभी समय लगना है, तो जल्दबाजी में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता क्या थी। विधायक ने इससे पहले वार्ड कमेटी ए के कार्यालय के उद्घाटन में भी प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासनिक कार्यक्रमों में नियमों और आधिकारिक शिष्टाचार का पालन होना चाहिए। स्नेहा दुबे-पंडित ने कहा कि मेयर शहर के प्रथम नागरिक होते हैं और उनसे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर संवैधानिक मर्यादा एवं प्रशासनिक नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

मॉ विंध्यवासिनी मित्रमंडल द्वारा आयोजित भव्य कलश यात्रा मातृशक्ति सम्मेलन 10 को

मुंबई (उत्तरशक्ति)। मुंबई के सायन कोलीवाड़ा न्यु म्हाडा कॉलोनी मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर मां विंध्यवासिनी मित्रमंडल के तरफ से दिनांक 10 अक्टूबर 2026 दिन शनिवार दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक भव्य कलश यात्रा एवं मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कलश यात्रा का प्रारंभ माता शितला देवी मंदिर, चर्च वाली गली सायन कोलीवाड़ा से होते हुए न्यु म्हाडा कॉलोनी स्थित मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर कलश यात्रा का समापन कर जलाभिषेक किया जायेगा। अतः सभी भक्त गणों से निवेदन है कि ठीक समय पर पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। यह जानकारी भरत भाई शुक्ला ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। अधिक जानकारी हेतु भरत शुक्ला से मोबाइल नंबर 9323807417 पर संपर्क कर सकते हैं।

कृपाशंकर सिंह ने दी विद्यासागर सोनकर को बधाई

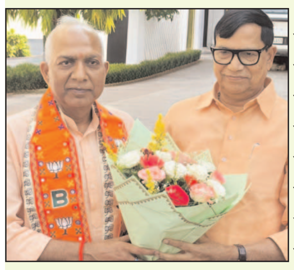

लखनऊ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री तथा जौनपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने पूर्व सांसद तथा विधान परिषद सदस्य विद्यासागर सोनकर को राज्यसभा निर्वाचन के लिए नामांकन के बाद बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कृपाशंकर ने कहा कि विद्यासागर सोनकर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता होने के साथ-साथ जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उन्होंने सोनकर का सम्मान करते हुए कहा कि श्री सोनकर एक कुशल संगठक तथा पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित जनप्रिय नेता हैं।

इस दिवाली परिवार के साथ यादगार गेटवे के लिए अबू धाबी को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करें

मुंबई। इस दिवाली अबू धाबी सैलानियों को हर पीढ़ी के लिए खास अनुभवों से भरपूर एक बेहतरीन फैमिली गेटवे का अवसर प्रदान कर रहा है। भारत के ज्यादातर प्रमुख शहरों से केवल तीन से चार घंटे की फ्लाइट से पहुँचा जा सकने वाला अबू धाबी, शॉर्ट गेटवे के साथ-साथ लंबी पारिवारिक छुट्टियों के लिए भी एक आकर्षक डेस्टिनेशन है। यूएई की राजधानी दादा-दादी से लेकर नाती-पोतों तक हर पीढ़ी के लिए खास अनुभव पेश करती है। यहां सफेद रेत वाले समुद्र तट, विश्वस्तरीय म्यूजियम, थीम पार्क, फेस्टिव शॉपिंग और फैमिली फीस्ट जैसे कई आकर्षण मौजूद हैं। इन हॉलीडे पैकेज की कीमत 83,325 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू होती है। फेस्टिव ब्रेक की तैयारी कर रहे परिवारों के लिए अबू धाबी में छुट्टियां बिताने के कुछ खास कारण इस प्रकार हैं। दिवाली पर ट्रैवल करना आपकी सोच से भी आसान है:भारत से केवल कुछ घंटों की फ्लाइट से अबू धाबी पहुँचा जा सकता है, जो क्विक गेटवे और लंबी फैमिली हॉलीडे, दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। परिवार छह रातों के पैकेज के साथ अबू धाबी में यादगार अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। यूटाजो का सिक्स-नाइट ह्नडिस्कवर अबू धाबी फेस्टिव सेलिब्रेशनह्न पैकेज 83,325 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू होता है। इसमें ब्रेकफास्ट के साथ एकोमोडेशन और एयरपोर्ट ट्रांसफर शामिल हैं। पैकेज में शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, लूवर अबू धाबी, यस आईलैंड के एक थीम पार्क और डेजर्ट सफारी का अनुभव शामिल है। साथ ही शॉपिंग के लिए भी पर्याप्त समय मिलता है। अहमदाबाद से यात्रा करने वाले परिवारों के लिए फ्लेमिंगो ट्रांसवर्ल्ड का ह्नदिवाली पैकेज इन एपिक टूर पैकेज क्रिस्ट व्यू 1,67,500 रुपये प्रति व्यक्ति से उपलब्ध है। इसमें रिटर्न इकॉनॉमी फ्लाइट, यूएई वीजा और अबू धाबी में तीन रातों का स्टे शामिल है। पैकेज में एमिरेट्स पैलेस मंडारिन ओरिएंटल में हाई टी, यस आइलैंड के दो थीम पार्क की विजिट, टीमलैब फेनोमेना अबू धाबी और शेख जायद ग्रैंड मॉस्क की विजिट भी शामिल है।

एआई चमकाएगी इंदौर की तस्वीर और तकदीर : महापौर पुष्यमित्र भार्गव

प्रणित नरेंद्र तिवारी

इंदौर (उत्तरशक्ति)। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. अब नगरीय निकाय और शहरों के विकास कार्यों में भी एआई का दखल हो रहा है. लिहाजा दुनिया के अन्य विकसित देशों की तुलना में भारतीय शहर भी एआई के लिहाज से अपग्रेड हो सके, इसे लेकर इंदौर को देश का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है.भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और नेपाल सहित आठ देशों के प्रतिनिधि अपने-अपने देश में जारी विकास कार्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर अपग्रेड करने की तैयारी में है. इस दिशा में भारत के तीन शहरों का सिलेक्शन केंद्र सरकार को करना है. इस बीच हाल ही में अमेरिका में आयोजित इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम के तहत भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर इंदौर नगर निगम के महापौर का सिलेक्शन हुआ, अमेरिकी दौरे के बाद मान जा रहा है कि देश के प्रमुख तीन शहरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब के रूप में इंदौर का चयन हो सकता है.अब अमेरिका से लौटकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर नगर निगम के कई प्रमुख कार्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपग्रेड किया. इसके साथ लोकल गवर्नेंस के कामकाज को अपग्रेड करने की तैयारी हैं. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, ₹ जल्द ही इंदौर को एआई का हब बनाया जाएगा. शहर के कई कार्यों को अपग्रेड भी किया जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि शहरों की गवर्नेंस शिक्षा उद्योग रोजगार परिवहन और नागरिक जीवन को प्रभावित करने वाली वास्तविकता है.₹उन्होंने आगे कहा, ₹ भारत के शहरों को भी अब एआई को समझ कर उसकी अवेयरनेस पर काम करना जरूरी है. इसके दुरुपयोग और जोखिम से बचने की भी लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए । क्योंकि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसे समझ कर नियंत्रित करके समाज के हित में इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है. इंदौर के पास इस दिशा में आगे बढ़ने की पर्याप्त क्षमता है.₹भविष्य में सभी को एआई के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी और परिवार से जुड़े सभी का एआई से प्रभावित होंगे. इसलिए इसे अभी से समझ कर उसके जोखिम पर नियंत्रण भी जरूरी है. इसके अलावा अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों में डिजिटल गवर्नेंस का तेजी से विस्तार हो रहा है. सुरक्षा के लिए कैमरे मॉनिटरिंग सिस्टम, वाहनों की निगरानी और ट्रैफिक मॉनिटरिंग में एआई कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है. इसके साथ ही शहरों की सुरक्षा तकनीक में इसका उपयोग सामने आया है. इससे प्राइवेसी भी प्रभावित होती है.

रोहियांव से श्रेया यादव लापता

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनपद जौनपुर विकास खण्ड सुजानगंज पोस्ट मधुपुर, थाना मुंगरा बादशाहपुर, ग्राम रोहियांव निवासी राकेश यादव (ललऊ यादव) की पुत्री श्रेया यादव उम्र 16 वर्ष दिनांक 3 अक्टूबर दिन शनिवार दोपहर 2 बजे से लापता हो गई है। परिवार जनों ने नात रिस्तेदारो के यहां पूछताछ किया लेकिन कोई पता नहीं चला तत्पश्चात थाना मुंगरा बादशाहपुर में गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन अभी तक श्रेया यादव की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। बच्ची की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।यदि किसी सज्जन को श्रेया यादव के बारे में जानकारी मिले तो कृपया मोबाइल नंबर 9305362172 , 7619817692 पर संपर्क करें। अथवा नजदीकी पुलिस स्टेशन में सुचना देने की कृपा करें। सुचना देने अथवा पहुंचाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा।

boAt ने एपेक्स पावरबैंक सीरीज लॉन्च की

मुंबई। भारत के प्रमुख कंज्यूमर लाइफस्टाइल-टेक ब्रांड्स में से एक **boAt** ने आज एपेक्स पावरबैंक सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की। इसके साथ कंपनी चार्जिंग सॉल्यूशंस कैटेगरी में अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रही है और ऑडियो से आगे अपने कंज्यूमर-टेक पोर्टफोलियो का लगातार विस्तार कर रही है। पर्सनल ऑडियो boAt के कारोबार का प्रमुख हिस्सा बना हुआ है, वहीं ब्रांड ने धीरे-धीरे वेयरेबल्स, प्रोजेक्टर्स, पर्सनल ग्रूमिंग और चार्जिंग सॉल्यूशंस जैसी संबंधित कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कैटेगरी में भी विस्तार किया है। यह विस्तार कंज्यूमर्स के कनेक्ट करने, काम करने, यात्रा करने और मनोरंजन का अनुभव लेने के तरीकों को ध्यान में रखते हुए एक विविध कंज्यूमर टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो तैयार करने कीुङ्मअ३ की व्यापक महत्वाकांक्षा को दशार्ता है। इस यात्रा में चार्जिंग सॉल्यूशंस एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभर रहे हैं। जैसे-जैसे कंज्यूमर्स दिनभर कई कनेक्टेड डिवाइसेज अपने साथ रखते हैं, भरोसेमंद और सुविधाजनक पावर एक्सेस रोजमर्रा के टेक्नोलॉजी अनुभव का अहम हिस्सा बन गया है। एपेक्स के साथुङ्मअ३ एक ऐसे चार्जिंग पोर्टफोलियो का निर्माण कर रहा है जो किसी एक प्रोडक्ट तक सीमित रहने के बजाय कंज्यूमर्स की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करता है।

ISB हर साल 250 स्कॉलरशिप देने और नेशनल रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा

ठाणे। फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग्स 2026 में भारत में पहले और दुनिया में 12वें स्थान पर रहे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर ISB@25 के तहत कई दीर्घकालीन पहलों की घोषणा की गई। इन पहलों का उद्देश्य मैनेजमेंट शिक्षा को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाना और भारत में रिसर्च और शिक्षण क्षमता को मजबूत करना है। ISB25 स्कॉलर्स प्रोग्राम के तहत क्यइ हर साल 250 स्कॉलरशिप देगा। ये स्कॉलरशिप क्यइ के प्रमुख पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (पीजीपी) और पीजीपी इन मैनेजमेंट फॉर यंग लीडर्स (पीजीपी वाईएल) कोर्स के लिए दी जाएंगी। स्कॉलरशिप छात्रों की योग्यता और आर्थिक जरूरत के आधार पर दी जाएगी। इसके तहत छात्रों को फीस में 100%, 50%, 30% और 25% तक की छूट मिलेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्यइ में अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को अवसर देना है। अलग-अलग आर्थिक, भौगोलिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाले होनहार छात्रों को विश्वस्तरीय मैनेजमेंट शिक्षा मिल सके, इसके लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके साथ ही ISB इंडिया रिसर्च कॉमन्स नाम से राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च प्लेटफॉर्म शुरू करेगा। इसके माध्यम से देशभर के स्कॉलर्स को चुनिंदा डेटा सेट, रिसर्च टूल्स, रिसर्च मेथडोलॉजी से जुड़े संसाधन और एआई आधारित रिसर्च सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही नया नेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से ISB देशभर के मैनेजमेंट शिक्षण संस्थानों के साथ अपनी शिक्षण पद्धति, क्लासरूम में पढ़ाने के तरीके और टेक्नोलॉजी की मदद से शिक्षा देने के तरीके साझा करेगा। इस तरह पिछले 25 सालों में ISB द्वारा विकसित क्षमताओं का लाभ देश के व्यापक शैक्षणिक क्षेत्र को मिल सकेगा। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन प्रोफेसर मदन पिल्लुतला ने कहा, "ISB@25 सिर्फ हमारे 25 साल के सफर का जश्न मनाने का मौका नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता तय करने का अवसर भी है। बेहतर शिक्षा को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाना, ज्ञान को अधिक लोगों के साथ साझा करना और देशभर की संस्थाओं और स्कॉलर्स के लिए रिसर्च को अधिक उपयोगी बनाना हमारा लक्ष्य है।

सिंटेक्स ने लॉन्च किया भारत में पहली बार 50 साल की वारंटी वाला एटर्नो वॉटर टैंक

सहरसा। वाटर स्टोरेज सॉल्यूशंस के क्षेत्र में भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांडों में से एक सिंटेक्स ने आज सिंटेक्स एटर्नो को लॉन्च किया। यह बेहतर मजबूती, स्वच्छता और लंबे समय तक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया अगली पीढ़ी का वॉटर टैंक है। इंडस्ट्री में पहली बार 50 साल की वारंटी जो भारत में अपनी तरह की एकमात्र वारंटी है, सिंटेक्स एटर्नो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीयता, सुरक्षा और निश्चिंतता का एक नया मानक स्थापित करता है। 100% फूड-ग्रेड वर्जिन प्लास्टिक से बना सिंटेक्स एटर्नो पानी का सुरक्षित और स्वच्छ स्टोरेज सुनिश्चित करता है। यह संदूषण या पानी में हानिकारक रसायनों के घुलने के जोखिम से पूरी तरह मुक्त है। भारत की विभिन्न जलवायविक स्थितियों में भरोसेमंद प्रदर्शन के लिए बना यह टैंक वातावरण की कठोर स्थितियों और लंबे समय तक धूप में रहने के बावजूद टिकाऊ बना रहता है। इसलिए इसका घरों, व्यावसायिक परिसरों और संस्थानों में हर जगह उपयोग किया जा सकता है। सिंटेक्स एटर्नो की सबसे बड़ी खूबी इसकी एक्टिव सिल्वर टेक्नोलॉजी है, जो सूक्ष्म जीवों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। यह तकनीक शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस की वृद्धि रोकती है, जिससे टैंक का पानी रोजमर्रा के उपयोग के लिए अधिक स्वच्छ और सुरक्षित बना रहता है। इसमें यूवी-प्रोटेक्टेड थ्रेडेड लिड दिया गया है, जो स्वच्छता को और बेहतर बनाता है और धूप से सीधा संपर्क सीमित करता है और बाहरी संदूषण से बचाता है। कठोर वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया सिंटेक्स एटर्नो आरओएचएस यूरोपीयन मानकों पर भी खरा उतरता है और एनएसएफ प्रमाणित है।

होटल व्यवसायियों की समस्या के निदान हेतु उप-प्रबंध निदेशक से मिले पूर्व साँसद गोपाल शेट्टी

मुंबई। महानगर गैस लिमिटेड के उप-प्रबंध निदेशक अजय सिन्हा संग बैठक करके पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने एमजीएल द्वारा व्यावसायिक पीएनजी उपभोक्ताओं के खिलाफ कथित मीटर में छेड़छाड़ का आरोप करने, कनेक्शन काटने, मीटर सील करने और पूर्वव्यापी जुमार्ना मांगने के संबंध में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए उन्हें एक पत्र भी सौंपा।

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित महानगर गैस निगम के मुख्यालय 'एमजीएल हाउस' में हुई इस बैठक में जनसेवक गोपाल शेट्टी संग होटल इंडस्ट्री के अनेक व्यवसायी, बैंक्वेट के मालिक व 'आहार' से जुड़े सदस्य शामिल थे।

जनसेवक गोपाल शेट्टी ने यहां सवाल उठाया कि यदि मीटर की हर 15 दिन में निगरानी की जाती है और बिल बनाए जाते हैं, तो कथित मीटर छेड़छाड़ कई महीनों या वर्षों तक एमजीएल को कैसे पता नहीं चल पाती है। छेड़छाड़ की पहचान 15 दिनों के भीतर ही हो जानी चाहिए, जिसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और उपभोक्ता को सूचित किया जाना चाहिए। MGL से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह महीनों या वर्षों तक चुप रहे और फिर अचानक उपभोक्ता पर बड़ी वित्तीय देनदारी थोप दे। यह पूरी तरह से गलत है। इस तरह की पूर्वव्यापी कार्रवाई, विशेष रूप से समय पर नोटिस, तकनीकी निष्कर्षों के खुलासे और सुनवाई के सार्थक अवसर के बिना, निष्पक्षता, पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जनसेवक शेट्टी ने आग्रह किया है कि एमजीएल तुरंत नए उत्पीड़न वाले नोटिस जारी करना बंद करे और सभी डिस्कनेक्शन, सीलिंग कार्रवाई और विवादित जुमार्ना वसूली को तब तक स्थगित रखे, जब तक कि प्रभावित उपभोक्ताओं के अभ्यावेदनों/पक्ष की ठीक से जांच और अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। बैठक के अंत में महानगर गैस लिमिटेड के उप-प्रबंध निदेशक अजय सिन्हा ने आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के भीतर ही वे इसका योग्य,ठोस व सार्थक हल निकालेंगे।

सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज प्रतियोगिता में स्कूली विद्यार्थी भी भाग लें : मंगल प्रभात लोढ़ा

मुंबई। केंद्रीय कौशल विभाग की ओर से ह्यसेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंजह्न बहुराज्यीय नवाचार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार विभाग, महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य के सभी स्कूली विद्यार्थियों को भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में कार्यरत सोलापुर स्थित स्टेट इनोवेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का सहयोग लिया जाएगा। नवाचार के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आएं, ऐसा आवाहन कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने किया।

मंत्रालय में ह्यसेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंजह्न प्रतियोगिता में राज्य के जिला परिषद एवं अन्य स्कूली स्तर पर विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोलापुर स्थित स्टेट इनोवेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन (सर) के साथ आयोजित बैठक में मंत्री श्री. लोढ़ा बोल रहे थे। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य नवाचार सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील, स्टेट इनोवेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के राज्य समन्वयक सिध्दराम माशाळे, बालासाहेब वाघ उपस्थित थे।मंत्री श्री. लोढ़ा ने कहा कि सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज प्रतियोगिता के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 17 अक्टूबर 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस प्रतियोगिता में नवप्रवर्तक, विद्यार्थी, विद्यार्थी समूह, शोधकर्ता, प्राध्यापक, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, कंपनियां, सामाजिक संस्थाएं, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाएं तथा अन्य इनोवेशन टीमें भाग ले सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों में स्थानीय समस्याओं को समझने और उनके रचनात्मक समाधान खोजने की क्षमता बड़े पैमाने पर है। यह क्षमता केवल स्कूली परियोजनाओं तक सीमित न रहकर वास्तविक समाजोपयोगी नवाचारों में परिवर्तित हो, यही ह्यसेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंजह्न का प्रमुख उद्देश्य है। विद्यार्थियों को समस्या की पहचान करने से लेकर उसका समाधान विकसित करने और उसे वास्तविक रूप से लागू करने तक मार्गदर्शन मिलना आवश्यक है। इस प्रतियोगिता में 10 प्रमुख क्षेत्रों के प्रत्येक 5 उपक्षेत्रों से नवाचारपूर्ण अवधारणाओं का चयन किया जाएगा। इस प्रकार कुल 50 विजेताओं को प्रत्येक को 10 लाख रुपये की वर्क ऑर्डर दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों की कल्पनाओं को केवल पुरस्कार ही नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें अपने नवाचार को वास्तविक रूप से लागू करने का अवसर भी उपलब्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की इस पहल में भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं (एनजीओ) को आगे आना चाहिए, ऐसा आवाहन मंत्री श्री. लोढ़ा ने किया। जिला परिषद की स्कूलों सहित ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न स्कूलों तक इस पहल की जानकारी पहुंचाकर विद्यार्थियों को इसमें सहभागी बनाना आवश्यक है। महिलाओं, युवाओं और सभी के लिए खुले विभिन्न वर्गों से अधिक से अधिक नवाचारपूर्ण विचार सामने आएं, इसके लिए प्रयास करने का आवाहन भी उन्होंने किया। कृषि, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, परिवहन सहित दैनिक जीवन की विभिन्न समस्याओं पर विद्यार्थियों को व्यवहार्य समाधान सुझाने चाहिए। एनजीओ को विद्यार्थियों को स्थानीय समस्याओं की पहचान करने, उनके समाधान विकसित करने और प्रतियोगिता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना चाहिए। अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली स्कूलों की संख्या, विद्यार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य, जानकारी दिए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा प्रस्तुत करवाए जाने वाले गुणवत्तापूर्ण आवेदनों की संख्या के संबंध में स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए।